नई दिल्ली
शुक्रवार
25 सितंबर 2026
वर्षः 13, अंकः 22
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

DELHIN/2014/58158

मजबूत टेस्ट टीम ही मजबूत क्रिकेट टीम, रेड-बॉल...पेज-06

बाढ़ प्रबंधन के लिए स्थायी समाधान की दिशा में...पेज-05

एक नजर

आरोग्य मंथन 2026 आज से, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) के आठ वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के पांच वर्ष पूरे होने की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। आरोग्य मंथन 2026 के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी कई नई पहलों की शुरुआत की जाएगी। इनमें सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट प्रमुख है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी डेटा के जिम्मेदार और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए बेहतर डिजिटल व्यवस्था तैयार करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी जानकारी के अनुसार एबीपीएम- जे एवाई के तहत 60 करोड़ से अधिक लाभार्थी कवर किए जा चुके हैं। योजना के माध्यम से अबतक 13 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनकी कुल राशि दो लाख करोड़ रुपये से अधिक है। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को योजना के दायरे में शामिल किए जाने से करीब छह करोड़ अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिला है। इस विस्तार का उद्देश्य बुजुर्गों के लिए इलाज के खर्च को लेकर वित्तीय सुरक्षा मजबूत करना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। अब तक 97.8 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) बनाए जा चुके हैं। वहीं, 121 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड इन डिजिटल खातों से जोड़े जा चुके हैं। डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था में 11 लाख से अधिक स्वास्थ्य पेशेवर भी जुड़े हैं। आरोग्य मंथन 2026 में इन उपलब्धियों के साथ-साथ देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, स्वास्थ्य डेटा के सुरक्षित उपयोग और नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने से जुड़े अगले चरण पर भी चर्चा होगी।

नशा मुक्त पंजाब अभियान का 30 सितंबर को जालंधर में समापन, शाह करेंगे विशाल जनसभा

नई दिल्ली। पंजाब में भाजपा की ओर से चलाए जा रहे 'नशा मुक्त पंजाब' अभियान का समापन 30 सितंबर को जालंधर में होगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अभियान के तहत राज्य के अलग-अलग हिस्सों से निकाली जा रही चार नशा विरोधी यात्राएं भी इसी दिन जालंधर में पहुंचकर एक साथ समाप्त होंगी। भाजपा सूत्रों ने बताया कि 30 सितंबर को चारों यात्राओं के जालंधर पहुंचने के बाद समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अमित शाह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जालंधर-फगवाड़ा हाई-वे के पास रैली के लिए स्थल तय किया जा चुका है और संगठन की स्थानीय इकाई ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट के माधोपुर से चार अलग-अलग मार्गों से 'नशा मुक्त पंजाब यात्राएं' शुरू की थीं। यह यात्राएं कुल 13 दिनों तक चलेंगी। इन यात्राओं को राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों तक पहुंचाने की योजना है। चारों यात्राएं मिलकर करीब 4,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं। पहली यात्रा की शुरुआत पठानकोट के माधोपुर स्थित एकता स्थल से हुई थी। अन्य यात्राएं फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और तलवंडी साबो से शुरू की गईं। अभियान का उद्देश्य नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इस मुद्दे पर व्यापक जनभागीदारी तैयार करना बताया गया है।

दिल्ली से महोबा जा रही बस में लगी आग, महिला सहित नौ लोगों की मौत

नोएडा,एजेंसी। दिल्ली के कश्मीरी गेट से उत्तर प्रदेश के महोबा जा रही एक डबल डेकर बस में बुधवार मध्य रात्रि यमुना एक्सप्रेस-वे के 33 किलोमीटर पर आग लग गई। बस में उसे समय 35 लोग सवार थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पुलिस, जिला प्रशासन की टीमों ने रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में एक महिला सहित नौ लोगों की जलकर मौत हो गई । इस घटना के चलते मध्य रात्रि से आज सुबह तक यमुना एक्सप्रेस-वे पर अफरा-तफरी मची हुई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने गैस कटर से बस को काटकर उसमें फंसे हुए शवों को बाहर निकाला।

अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि एक डबल डेकर बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से 35 सवारियों को भरकर बुधवार की मध्य रात्रि को यमुना एक्सप्रेस-वे के रास्ते महोबा जनपद के लिए रवाना हुई। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे के 33 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते बस में अचानक आग लग गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर दमकल विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि रेसक्यू करने के बाद करीब 26 लोगों को बाहर निकला गया, जबकि एक महिला सहित नौ लोगों की जलने से मौत हो गई है। कुछ लोग बस में भरे धुएं की वजह से बेहोश हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत अब ठीक है। उन्होंने बताया कि आगजनी के चलते बस में पूरी तरह से धुआं भर गया था। घटना के समय कुछ लोग सो रहे थे। उन्होंने बताया कि काफी लोग सोने की वजह से बस में फंस गए तथा उनकी जलने से मौत हो गई। अपर आयुक्त ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने बस का शीशा तोड़कर और गैस कटर से बस के काफी हिस्से को काटा तथा उसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की पहचान हुई है लेकिन अभी तक कुछ की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सभी लोगों की पहचान कराकर उनके परिजनों को सूचना देने का प्रयास कर रही है। बस में सवार रिंकी राजपूत ने बताया कि वह डबल डेकर नोएडा बस में नोएडा से सवार हुई थी तथा तथा अपने घर राठ जा रही थी। घटना के समय वह सो रही थी। किसी यात्री ने उनके केबिन को जोर-जोर से पीट कर जगाया। उसके बाद बस के बाहर निकली। उन्होने बताया कि लोगों में इतनी अफरा-तफरी थी कि किसी ने अपना सामान भी नहीं उठाया। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। इस घटना में काफी लोगों का समान, नकदी, जेवर, मोबाइल फोन आदि भी जल गया है। उन्होंने बताया कि घटना के करीब आधे घंटे बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। बस में सवार रिंकी के अनुसार इस घटना में नौ लोगों से ज्यादा की मरने की आशंका है।

योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद

लखनऊ,हि.स.। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस में आग लगने की घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और उन्हें हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों से बात कर सहायता का भरोसा दिलाया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ग्रेटर नोएडा में बुधवार देर रात जेवर क्षेत्र में दयानतपुर गांव के पास दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ यात्री बस के भीतर फंस गए। पुलिस और बचाव दल ने करीब 30 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में नौ यात्रियों की मौत हुई है।

ज्ञानेश कुमार तत्काल इस्तीफा दें, वोट चोरी देशद्रोह है: राहुल

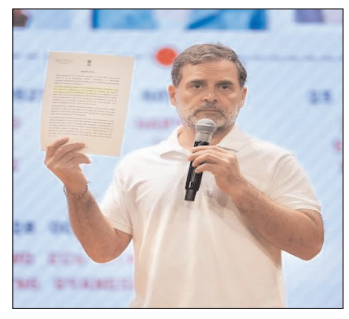

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 'वोट चोरी' कराई है और उनको तत्काल इस्तीफा देकर सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। श्री गांधी ने यहां पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कई तरह से 'वोट चोरी' की साजिश कर देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और इस साजिश में जो भी संलिप्त हैं वे सब देशद्रोही हैं और उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस पूरी साजिश के केंद्र में हैं और उन्होंने देश के साथ जो किया है भविष्य में उसकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर जो सवाल उठाये हैं, वह सही कदम है और वह इसकी सराहना करते हैं।

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा कि वह वोट चोरी में शामिल हैं इसलिए उनको सलाह है कि वह अपने काम तथा अपने पद की गरिमा के बारे में गंभीरता से सोचें और सरकारी गवाह बन जायें। उनका कहना था कि श्री ज्ञानेश कुमार का ऐसा करना देशहित में होगा। उन्होंने कहा कि भारत में सत्ता-विरोधी लहर एक ऐसी बुनियादी राजनीतिक शक्ति है जो किसी भी सरकार को नहीं छोड़ती। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब बंगलादेश युद्ध जीता और उनकी लोकप्रियता तब चरम पर थी लेकिन एक-दो वर्ष के भीतर ही उनके खिलाफ जबरदस्त सत्ता-विरोधी लहर आ गयी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के साथ भी यही हुआ। यह हर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के साथ भी होता है लेकिन श्री मोदी, श्री शाह और भाजपा के खिलाफ यह सत्ता-विरोधी लहर दिखाई नहीं देती। किसी व्यक्ति की लोकप्रियता और सरकार के प्रदर्शन को समझा जा सकता है लेकिन सत्ता-विरोधी लहर कैसे गायब हो गयी, यह समझ में नहीं आता। गांधी ने कहा कि गृहमंत्री दावा करते हैं कि 30 साल तक भाजपा सत्ता में रहेंगे, लोगों को आदत डालनी चाहिए। उनका कहना था कि वह करीब 50 वर्ष से राजनीति को करीबी से देख रहे हैं और किसी भी राजनीतिक माहौल में कोई भी नेता इस तरह की बात नहीं कर सकता कि उसकी सरकार कई वर्षों तक बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के बावजूद कुछ ही वर्षों में सत्ता-विरोधी लहर आयी और देश के अनेक प्रधानमंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों को इसका सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सत्ता-विरोधी लहर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि यह शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को प्रभावित क्यों नहीं करती और उन्हें लगता है कि इसका जवाब दो चुनाव आयुक्तों ने दिया है। उन्होंने कहा कि वोट देश की बुनियाद है और चुनाव आयोग का काम इसकी रक्षा करना है।

बैकों की हड़ताल के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन भुगतान 25 सितंबर को करने का निर्देश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सितंबर माह की सैलरी और पेंशन का भुगतान 25 सितंबर को ही जारी करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 23 सितंबर को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सैलरी और पेंशन का भुगतान जल्दी करने की जानकारी दी। व्यय विभाग ने बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को देखते हुए मंत्रालयों एवं विभागों को निर्धारित समय से पहले 25 सितंबर को ही सैलरी का भुगतान करने को कहा है।

मंत्रालय ने कहा कि आदेश के अनुसार तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के दौरान बैंकिंग लेनदेन (ट्रांजैक्शन) में रुकावट की संभावना को देखते हुए सैलरी, मजदूरी और पेंशन के भुगतान में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। 28 से 30 सितंबर तक होने वाली तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सितंबर, 2026 की सैलरी और पेंशन 25 सितंबर को ही मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28-30 सितंबर की तीन-दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया हुआ है। बैंक यूनियनों की मुख्य मांग में पांच कार्यदिवस वाले सप्ताह की व्यवस्था को लागू करने की है।

ज्ञानेश कुमार ने दो दिनों में इस्तीफा नहीं दिया तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा : सीजेपी

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए गुरुवार को कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर श्री कुमार ने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो पार्टी देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी और उनके इस्तीफे के बिना पीछे नहीं हटेगी। सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि श्री कुमार के चुनाव आयुक्त बनने के बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि पश्चिम बंगाल में 97 लाख लोगों को मतदान से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अब तक 13 करोड़ वोट हटाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और हारने वाले इंडिया गठबंधन के बीच सिर्फ तीन प्रतिशत का अंतर था।

विविधता में एकता के अनुभव को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाएं: मोदी

बीकानेर,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को सेवा संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों का आह्वान किया कि वे यात्रा के दौरान लिये गये विविधता में एकता के अनुभव को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाएं। श्री मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि गांव-कस्बे ज्ञान और समाधान का समृद्ध खजाना है। एक गांव का प्रयोग दूसरे गांव के काम आएगा और एक युवा का समाधान दूसरी युवा की ताकत बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत में यात्रा और सेवा दोनों ही सामाजिक संस्कार से जुड़े रहे हैं। एक व्यक्ति और एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर इन यात्राओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये यात्राएं करुणा, विनम्रता और अनुशासन सिखाती हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है।

श्री मोदी ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारी परंपरा भी नर सेवा नारायण सेवा की है। जब शासन के मूल में सेवा का भाव होता है, तो हर नीति के केंद्र में 'नागरिक देवो भव' का संकल्प होता है।

यही सेवा भाव देश की नीतियों में लागू होता है तभी देश आगे बढ़ता है। नयी-नयी योजनाएं जन्म लेती हैं। करोड़ों जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज और आयुष्मान जैसी योजनाओं के मूल में सेवा का भाव ही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता है। इसके लिए उन्हें देश को समझना, सामाजिक वर्गों से मिलना और उनकी आकांक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है। इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाने वाली है। इसके प्रतिभागी जहां भी जा रहे हैं, वहां संवाद और जनभागीदारी के सेतु बना रहे हैं। सेवा भाव से किया गया हर काम याद रखा जाता है। इससे पहले श्री मोदी ने सेवा संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करके उनके अनुभव जाने। इस दौरान उन्होंने ब्यावर से डॉक्टर देवांगी और डेगाना से हर्षवर्धन सिंह एवं कुलदीप से संवाद किया।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने मेगा स्वास्थ्य जांच का किया शुभारंभ, बोलीं- नहीं तोड़ी जाएगी एक भी झुग्गी

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के हैदरपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त दिल्ली की नींव हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के झुग्गीवासियों से संवाद करते हुए उनके आवास को लेकर व्यक्त की जा रही चिंताओं पर भी स्पष्ट आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। वर्षों से कठिन परिस्थितियों में रह रहे झुग्गीवासियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में हैदरपुर क्षेत्र के एयू ब्लॉक और एओ ब्लॉक की झुग्गियों के लिए आवास निर्माण से संबंधित टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन क्षेत्रों के आसपास उपयुक्त स्थान चिन्हित कर वहां आवास निर्माण का कार्य किया जाएगा। दूसरे चरण में आयुर्वेदिक अस्पताल क्षेत्र की झुग्गियों को शामिल किया जाएगा और आसपास उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है ताकि झुग्गीवासियों के लिए उनके क्षेत्र के नजदीक बेहतर आवास उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को हटाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है।

भारत-नीदरलैंड का जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने पर जोर

गुजरात के कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण पर दो त्रिपक्षीय समझौते

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और नीदरलैंड ने जल क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तकनीकी सहयोग एवं क्षमता निर्माण पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच गुरुवार को हुई बैठक में गुजरात की कल्पसर परियोजना में सहयोग के लिए केंद्रीय जल आयोग, गुजरात सरकार के कल्पसर विभाग और नीदरलैंड के जल संबंधी शोध संस्थान डेल्टारेस एवं डेल्फ्ट तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच दो त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और नीदरलैंड के बुनियादी ढांचा एवं जल प्रबंधन उपमंत्री जैप स्लूटमेकर ने भारत मंडपम में 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह-2026 के दौरान बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गुजरात की कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री राज भूषण चौधरी, गुजरात के जल संसाधन एवं जलापूर्ति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ईश्वरसिंह पटेल, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक केके मीणा, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सचिव अर्चना वर्मा, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष अनुपम प्रसाद तथा भारत में नीदरलैंड की राजदूत मारिसा गेराड्स सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री पाटिल ने कहा कि डेल्टारेस और डेल्फ्ट विश्वविद्यालय का भारतीय संस्थाओं के साथ समझौता करना कल्पसर परियोजना के क्रियान्वयन तथा क्षमता निर्माण में सहयोग को और गहरा करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ये समझौते दोनों देशों को परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम करने का मजबूत आधार प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मई 2026 में नीदरलैंड यात्रा के दौरान कल्पसर परियोजना पर चर्चा हुई थी। इसके बाद 16 मई 2026 को तकनीकी सहयोग के लिए आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किए गए थे। पाटिल ने बताया कि कल्पसर परियोजना में साबरमती, माही और धाधर नदियों के बहाव से प्राप्त पानी का उपयोग कर मीठे पानी का जलाशय बनाने की परिकल्पना है। इसमें नर्मदा नदी से पहुंचाए जाने वाले पानी को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुलाई 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की नीदरलैंड यात्रा के दौरान बाढ़ सुरक्षा, तटीय बुनियादी ढांचे, हाइड्रोलिक मॉडलिंग, स्लुइस और पंपिंग प्रणालियों, तटबंध प्रौद्योगिकी तथा पारिस्थितिक समाधान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

नदियां हमारे जनमानस की आत्मा, संस्कृति और जीवन-धारा को भी वहन करती हैं: तरनजीत संधू

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को कहा कि नदियां हमारे जनमानस की आत्मा, संस्कृति और जीवन-धारा को भी वहन करती हैं। उपराज्यपाल तरनजीत संधू आज दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में आयोजित 24 से 26 सितंबर तक 7वें 'नदी उत्सव' को संबोधित कर रहे थे। इस वर्ष के उत्सव की मुख्य थीम 'यमुना नदी' पर केंद्रित है। तीन दिवसीय इस उत्सव का उद्देश्य नदियों के महत्व, उनके संरक्षण और सांस्कृतिक सरोकारों को जन-जन तक पहुंचाना है।

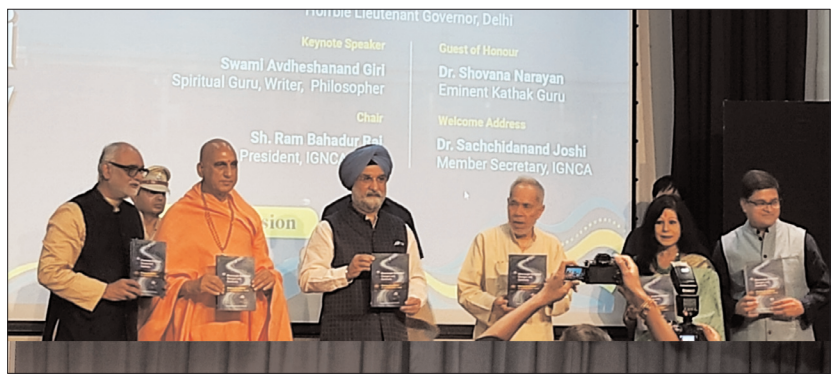

मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कहा, 'हमारी सभ्यतागत समझ में, नदी एक पवित्र और जीवनदायिनी शक्ति है जो समुदायों, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) का भरण-पोषण करती है। लेकिन अब यमुना शहरीकरण, प्रदूषण तथा शहर और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच बदलते संबंधों के चलते भारी दबाव का सामना कर रही है। यदि हम इस नदी को अपनी सांस्कृतिक विरासत का अंग मानते हैं, तो इसका संरक्षण करना भी हमारी धरोहर और भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है।' संधू ने कहा कि नदी का स्वास्थ्य केवल जल शोधन से संभव नहीं है। इसके लिए कचरे और अनुपचारित सीवेज को नदी में गिरने से रोकना तथा आसपास के शहरी व प्राकृतिक तंत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड और 'नमामि गंगे' जैसी पहलों को सफल बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों का एकजुट होना आवश्यक है, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए पुनर्जीवित किया जा सके। उपराज्यपाल ने कहा कि तीन दिवसीय नदी उत्सव जागरूकता को प्रगाढ़ करेंगे, सहभागिता को बढ़ावा देंगे और यमुना के अनवरत पुनरुद्धार के लिए नए विचारों को जन्म देंगे। स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा कि हम यमुना नदी के उत्सव के साथ-साथ एक और संकल्प ले रहे हैं कि हम यमुना को इस तरह से बनाना चाहेंगे कि वहां स्नान हो सके और आचमन हो सके। इस नदी उत्सव का मुख्य संकल्प यही होना चाहिए कि यमुना को दिल्ली में भी वैसा ही निर्मल बनाया जाए, जैसी वह हिमालय और विकासनगर में बहती है। उन्होंने कहा कि नदियां दो प्रकार से जन्म लेती हैं, एक ग्लेशियर (हिमरैणु) से और दूसरी वृक्षों की जड़ों से। ऐसे में वनों और वनस्पतियों का संरक्षण नदियों के सातत्य और प्रवाह के लिए अनिवार्य है। उन्होंने मांग की कि सरकार स्तर पर एक सशक्त टास्क फोर्स का गठन हो और समाज मिलकर अपनी नदियों, सरोवरों और जल-परंपरा को बचाने के लिए आगे आए। कथक नृत्यांगना पद्म शोवना नारायण ने कहा कि नदी केवल एक भौगोलिक जलधारा नहीं है, बल्कि यह पीढ़ियों को जोड़ने वाली स्मृति, संस्कृति और संस्कार की अविरल चेतना है। समाज के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज नदियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण आत्मचिंतन की मांग करता है। एक ओर हम नदियों को पूजते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें निरंतर प्रदूषित भी करते जा रहे हैं। जब तक इस विरोधाभास को स्वीकार कर जनचेतना में बदलाव नहीं लाया जाएगा, तब तक नदियों का वास्तविक संरक्षण संभव नहीं है।

उत्सव के पहले दिन शाम 06:30 बजे - 07:30 बजे विष्णुप्रिया गोस्वामी और उनकी टीम ने ओडिसी नृत्य और हवेली संगीत का एक अनूठा संगम प्रदर्शित किया। तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में युवाओं के लिए वाद-विवाद, स्केचिंग और कार्टून मेकिंग जैसी कई रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा कई सत्र आयोजित किए जाएंगे और साथ ही डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म फेस्टिवल में अलग-अलग भाषाओं फिल्में दिखाई जाएंगी। इसका मुख्य विषय 'रिवर एज़ एन आर्काइविस्ट' रखा गया है। इसमें जाने-माने फ़िल्मकारों के साथ आईजीएनसीए द्वारा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा और यमुना पर निर्मित वृत्तचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नदियों पर मौलिक काव्य लेखन प्रतियोगिता होंगी। प्रदर्शनियां प्रदर्शित की जाएंगी। नदियों का प्रवाह तलाशने और उनके संरक्षण में जुटे देश के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को परिचर्चा के लिए एक मंच पर लाया जाएगा। इसमें देशभर के करीब 50 विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस वर्ष युवा पीढ़ी को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने 2 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी 'विशेष अभियान 6.0' की व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रालय के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों को फाइलों के बोझ से मुक्त करना, कार्यस्थल पर स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान करना है। इसको प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) संचालित कर रहा है।

अभियान के सुचारू संचालन के लिए दो चरण निर्धारित किए गए हैं। पहले चरण में 16 से 30 सितंबर (लंबित मामलों व अनुपयोगी सामग्री की पहचान) तक तैयारी और दूसरे चरण में 2 से 31 अक्टूबर (निपटान और स्वच्छता गतिविधियां) तक कार्यान्वयन होगा। विभाग ने अभियान को धरातल पर उतारने के लिए आंतरिक स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित कर दिया है। साथ ही अपने सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि वे भी नोडल अधिकारी नियुक्त करें और डीएआरपीजी के तय मानकों के अनुरूप स्क्रैप, ई-कचरे और लंबित फाइलों को चिह्नित करें। विभाग पिछले वर्ष (अक्टूबर 2025) चलाए गए 'विशेष अभियान 5.0' की उपलब्धियों को इस बार और विस्तार देने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले अभियान के मुख्य परिणामों में 11,972 भौतिक फाइलों और दस्तावेजों का निस्तारण एवं डिजिटलीकरण, अनुपयोगी सामग्री हटाकर लगभग 15,588 वर्ग फुट कार्यालयी स्थान खाली कराया गया, कबाड़ एवं अनुपयोगी सामान के निपटान से 14,47,619 रुपये का राजस्व प्राप्त करना तथा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 64 इनडोर और आउटडोर स्वच्छता अभियान शामिल है। हर महीने चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की प्रगति रिपोर्ट को विशेष अभियान पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक 'विशेष अभियान 6.0' के तहत विभाग का मुख्य फोकस अप्रचलित कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ई-कचरे के सुरक्षित एकत्रीकरण, पृथक्करण और जिम्मेदारीपूर्ण निपटान पर रहेगा। विभाग का उद्देश्य निष्क्रिय संसाधनों और फाइलों के अंबार को दक्षता, पारदर्शिता और बेहतर कार्यस्थल संस्कृति में बदलना है।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
सत्यमेव जयते

दिल्ली के पार्कों में पुलिस की सख्ती, 111 पर कार्रवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के कई पार्कों और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं समेत आम लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिला पुलिस ने गश्त और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान 111 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी।

पुलिस के अनुसार संवेदनशील स्थानों पर लगातार पुलिस की मौजूदगी बनाए रखकर असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। मध्य जिले के अलग-अलग पार्कों में गहन जांच के दौरान 111 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत कार्रवाई की। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली के पार्कों का सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय जिले में पुलिस ने पार्कों के अलावा बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाकों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर संयुक्त फुट पेट्रोलिंग की। अभियान में केंद्रीय जिला पुलिस के साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और आउटर फोर्स के जवानों को भी लगाया गया। पुलिस टीमों ने पार्कों में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों की जांच की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। खासतौर पर उन सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है, जहां महिलाओं और आम लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। पुलिस ने कहा कि अभियान का मकसद केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाकर अपराध की आशंका को कम करना है।

महापौर ने हिंदूराव अस्पताल का किया निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गुरुवार को हिंदूराव अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं, व्यवस्थाओं एवं विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल, अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ सुमनलता मेहंदी रत्ता, उपायुक्त कनिका सहित निगम एवं अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। महापौर ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक, विभिन्न वार्डों, बाल चिकित्सा आपातकालीन ब्लॉक, आईसीयू तथा लेबर रूम का दौरा किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में भर्ती एवं उपचार करा रहे मरीजों से सीधे बातचीत कर उनके स्वास्थ्य, उपचार व्यवस्था तथा अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

महापौर ने विशेष रूप से मरीजों से दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश

दिए कि मरीजों को आवश्यक दवाइयां समय पर उपलब्ध हों। उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और अस्पताल परिसर एवं वार्डों में स्वच्छता का स्तर और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्डों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एलईडी लाइट लगाने तथा टूटी हुई बेंचों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। अस्पताल में सड़क की स्थिति का निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रोड की आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए। महापौर ने लेबर रुम में किए गए उन्नयन कार्यों का निरीक्षण करते हुए वहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने लेबर रुम में लगाए गए सीटीजी मॉनिटर्स का भी जायजा लिया। साथ ही बाल चिकित्सा आपातकालीन ब्लॉक तथा अन्य वार्डों के उन्नयन कार्यों की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि हिंदूराव अस्पताल का लगातार उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि दिल्लीवासियों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

उन्होंने बताया कि अस्पताल में नई मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं तथा नए ब्लॉक का भी उद्घाटन किया गया है। अस्पताल की आईसीयू की क्षमता 8 बेड से बढ़ाकर 18 बेड की जा रही है, जिसका कार्य प्रगति पर है। इससे गंभीर मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल के पुराने एवं जर्जर रेजिडेंस ब्लॉक को हटाकर उसके स्थान पर नया वार्ड ब्लॉक विकसित करने की योजना है, जिसमें लगभग 200 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पुराने लॉन्ड्री ब्लॉक को हटाकर वहां रेजिडेंस ब्लॉक को स्थानांतरित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।

आस्था कुंज पार्क गैंगरेप मामला: तीन आरोपित न्यायिक हिरासत में भेजे गए

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आस्था कुंज पार्क गैंग रेप मामले के तीन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज तीनों आरोपितों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जिन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया उनमें हेमंत, मुकेश और आसिफ शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। आरोपित आसिफ के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है जिसमें पुलिस टीम की जानलेवा हमले की कोशिश का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तीन सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले थे। उनमें से 20 लोगों की तकनीकी निगरानी की गई। स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से तीन आरोपितों को चिन्हित किया गया। ये तीनों आरोपित अक्सर पार्क आते-जाते रहते हैं। घटना 21 सितंबर की शाम सवा सात बजे से आठ बजे के बीच की है जब तीनों आरोपितों ने लड़की और उसके 17 वर्षीय दोस्त को गेट नंबर 7 से पार्क में प्रवेश करते देखा। उन्होंने लगभग एक किलोमीटर तक उनका पीछा किया और फिर उन्हें रोक लिया। उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दोनों को धमकाया और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की चेतावनी दी। इसके बाद आरोपितों ने लड़की को उसके दोस्त से कथित तौर पर अलग कर दिया। आसिफ पर आरोप है कि उसने चाकू और पिस्तौल दिखाकर धमकाया, जबकि दो आरोपित लड़की को पार्क के अंदर सूनसान जगहों पर ले गए और वहां लड़की का यौन उत्पीड़न किया।

मालवीय नगर अग्निकांड: आरोपित होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 01 अक्टूबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपित एवं होटल मैनेजर जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 01 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) भानु प्रताप सिंह ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। इस मामले में दो आरोपित जमानत पर हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को होटल मालिक लवकेश बजाज को स्वास्थ्य के आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी और साकेत कोर्ट ने केसर नेगी को 27 जुलाई को जमानत दी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 01 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। 03 सितंबर को साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज, होटल के मैनेजर जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 326(जी), 324(5), 125 और 287 के तहत आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को 04 जून को और केसर नेगी को 06 जून को गिरफ्तार किया था। 08 जून को जय मिश्रा ने भी कोर्ट में सरेंडर किया था। मालवीय नगर के होटल में 03 जून को सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 22 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी थे। बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे।

एससी-एसटी मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सौरभ बनर्जी ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर 16 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वह विवादित वीडियो देखा था, जिसमें भारती ने कथित तौर पर कुछ टिप्पणियां की थीं। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट को बताया गया कि एफआईआर 25 अगस्त को दर्ज की गई थी। तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया। क्या आपको पूछताछ की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष बालकराम बौद्ध ने अजीत भारती के खिलाफ 23 अगस्त को नॉर्थ एवेन्यू थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर एससी-एसटी एक्ट, आईटी एक्ट की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता की धारा 196(1)(सी) के तहत दर्ज की गई थी। एफआईआर में बालकराम बौद्ध ने अजीत भारती के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर दर्ज कराई थी। बौद्ध की शिकायत में कहा गया है कि अजीत भारती ने जाति-आधारित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत में कहा गया है कि अजीत भारती ने वीडियो में बीआर अंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके अलावा भारती ने महिलाओं के बारे में यौन रुप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और कथित रुप से धमकियां दी। हालांकि, अजीत भारती ने सार्वजनिक रुप से अपना बचाव करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां उनके वीडियो पर उनकी मां-बहन के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी के जवाब में थीं। भारती की अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया था कि ये टिप्पणियां एक व्यक्ति द्वारा की गई गंभीर उकसावे वाली बात के बाद की गई थीं, जिसमें टिप्पणी की गई थी कि भारती की शादीशुदा बहन को किसी दूसरे व्यक्ति (चंद्रशेखर रावण) से शादी कर लेनी चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय: महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अभाविप का वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हालिया घटनाओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने आर्ट्स फैकल्टी स्थित कुलपति (वीसी) कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने दिल्ली पुलिस, विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तत्काल कड़े और प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

कार्यकर्ताओं ने हाल की घटनाओं पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों में राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा ने पूरे छात्र समुदाय को झकझोर दिया है। संगठन ने लेडी श्रीराम (एलएसआर) कॉलेज के बैक गेट के पास दुष्कर्म के मामले, विजय नगर क्षेत्र में छात्राओं से छेड़छाड़ तथा जेएनयू में बाहरी तत्वों को लेकर दर्ज कराई गई शिकायतों का हवाला देते हुए परिसरों की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। अभाविप दिल्ली पुलिस से यह माँग करती है कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर फास्टट्रैक कोर्ट में केस चलाकर सख्त से सख्त करवाई की जाए। अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों

में महिलाओं और छात्राओं के साथ सामने आई घटनाओं ने पूरे छात्र समुदाय को आहत किया है। विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास छात्राओं को भयमुक्त वातावरण मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार आपसी समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल मजबूत करें। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और त्वरित शिकायत निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, नियमित पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, खराब स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी को तत्काल दुरुस्त किया जाए तथा छात्राओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।

दिल्ली: फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार

नई दिल्ली। अमेरिका में बैठे लोगों को टेक सपोर्ट के नाम पर ठगने वाले गिरोह का आईएफएसओ ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पीतमपुरा में किराये के मकान में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापा मारकर दो महिलाओं समेत 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 41 लाख रुपये नकद, 29 लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन, आठ राउटर और एक कार बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने विदेश में बैठे पीड़ितों से करीब 100 करोड़ रुपये की ठगी की है।

आईएफएसओ को 21 सितंबर को पीतमपुरा इलाके में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलने की सूचना मिली थी। एसीपी प्रेमचंद्र खंडूरी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर दाताराम समेत पुलिस टीम ने शिवाजी मार्केट, पितमपुरा गांव स्थित मकान नंबर 249 की तीसरी और चौथी मंजिल पर छापा मारा। वहां 11 लोग कॉल सेंटर चला रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि ये लोग अमेरिका के लोगों को टेक सपोर्ट कर्मचारी बनकर फोन करते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह का बैकएंड नेटवर्क पहले अमेरिकी नागरिकों के कंप्यूटर में मालवेयर पहुंचाता था। इसके बाद उनकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप आता था, जिसमें तकनीकी मदद के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करने को कहा जाता था। पीड़ित के कॉल करने पर उसे पीतमपुरा स्थित कॉल सेंटर में बैठे एजेंटों के पास पहुंचाया जाता था। एजेंट तय स्क्रिप्ट के अनुसार पीड़ित को बताते थे कि उसके कंप्यूटर में वायरस है और बैंक खाते भी खतरे में हैं। इसके बाद अल्ट्रा व्यूअर इंस्टॉल करवाकर कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस हासिल कर लेते थे। फिर पीड़ित की कॉल कथित फर्जी बैंक अधिकारी के पास ट्रांसफर कर दी जाती थी। फर्जी बैंक अधिकारी अमेरिकी नंबरों से संपर्क कर पीड़ितों को आईट्यून्स, सेफोरा, टारगेट और गूगल पे के गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए कहते थे। कुछ मामलों में बिटकॉइन के जरिए रकम भेजने को भी कहा जाता था।

एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में जनहित से जुड़े कई प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की बैठक में गुरुवार को जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के दौरान पक्ष एवं विपक्ष दोनों के पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं, मुद्दे एवं सुझाव रखने का पूरा अवसर दिया गया। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति लोकतांत्रिक संवाद तथा जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्षदों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में पार्षदों द्वारा सफाई व्यवस्था, जोन में सफाई कर्मचारियों की कमी, अवैध प्ले स्कूल, सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, बेसहारा पशुओं की समस्या, पार्कों के रखरखाव तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विषय प्रमुखता से उठाए गए। सत्या शर्मा ने सभी जोन के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में जर्जर एवं असुरक्षित इमारतों का सर्वे कराया जाए। ऐसी इमारतों की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए तथा जहां आवश्यक हो, वहां नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े

मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जोन में कार्यरत नियमित एवं अस्थायी/अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। सूची के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा, ताकि जहां कर्मचारियों की कमी है, वहां आवश्यकतानुसार व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी करने तथा कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुरूप क्षेत्रों में प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में एक जनप्रतिनिधि द्वारा अपने क्षेत्र में लंबे समय से संचालित पुरानी पार्किंग को बंद किए जाने से संबंधित विषय भी उठाया गया। इस संबंध में बताया गया कि पार्किंग व्यवस्था से जुड़े मामलों में स्थानीय यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि किसी स्थान पर वर्तमान पार्किंग व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता हो, तो वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विचार किया जाए, ताकि पार्किंग बंद होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया एवं निविदा संबंधी कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति का उद्देश्य केवल प्रस्ताव पारित करना नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में उठाए गए जनहित के विषयों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए तथा संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाए।

एक नजर

युवाओं को इनोवेशन व स्किल के साथ उद्योग से जुड़ना होगा: डॉ. प्रशांत कुमार

गुरुग्राम। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के पर्यटन एवं आतिथ्य विभाग द्वारा गुरुवार को विश्व पर्यटन दिवस-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कुलपति प्रो. (डॉ.) संजय कौशिक के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय परिसर सेक्टर-87 में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विभाग की अध्यक्षा डॉ. सुरभि गोयल ने किया। इस अवसर पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के निदेशक प्रो. (डॉ.) प्रशांत कुमार गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एफसीएम की डीन एवं डीन अकादमिक अफेयर्स प्रो. (डॉ.) अमरजीत कौर और कुलसचिव डॉ. संजय अरोड़ा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर दौरान पर्यटन क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका, टिकाऊ पर्यटन और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) प्रशांत कुमार गौतम ने पर्यटन उद्योग की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बदलते समय में टेक्नोलॉजी और एआई पर्यटन के स्वरूप को बदल रहे हैं, ऐसे में युवाओं को इनोवेशन और स्किल के साथ उद्योग से जुडना होगा। उन्होंने छात्रों को पर्यटन क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर विभाग के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पर्यटन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार सांझा किए।

27 सितंबर को हरियाणा की नई राजनीति का उदय होगा : आदित्य देवीलाल चौटाला

नूंह। जननायक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 131वीं जयंती को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की ओर से मेवात की धरती पर 27 सितंबर को आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डबवाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान आदित्य देवीलाल चौटाला ने कहा कि मेवात की इस पावन धरा पर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 131वीं जयंती इनेलो परिवार द्वारा मनाई जा रही है। समारोह में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर करीब 75 एकड़ भूमि में लोगों के बैठने के लिए विशाल टेंट लगाया गया है। इसमें ढाई लाख से तीन लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि समारोह में आने वाली भीड़ को देखते हुए उन्हें लगता है कि 27 सितंबर को यह स्थान भी छोटा पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोग जननायक चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने और समारोह में शामिल होने के लिए मेवात पहुंचेंगे। आदित्य चौटाला ने कहा कि उनकी उम्र 49 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा पंडाल न तो कभी देखा है और न ही उन्हें लगता है कि इससे बड़ा पंडाल कहीं लगा होगा। उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर समारोह की तैयारियां की गई हैं, उससे साफ है कि 27 सितंबर का आयोजन ऐतिहासिक होने जा रहा है। इनेलो विधायक ने कहा कि 27 सितंबर का दिन हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए किसी पर्व से कम नहीं होगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश से लोग मेवात पहुंचेंगे। रैली स्थल को अपनी जमीन देने वाले किसान जैकम खान ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी दवीलाल के जन्मदिन के लिए उनकी जमीन को चुना गया उन्होंने कहा कि उनके लिए यह एक गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर हरियाणा के इतिहास को बदलने का दिन होगा और इसी दिन हरियाणा की नई राजनीति का उदय होगा। समारोह को लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है।

साहिबाबाद में प्रेमी के चक्कर में बहू ने ससुर पर ताना चाकू, वीडियो बनाने पर देवर का मोबाइल तोड़ा

साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में 71 वर्षीय ससुर को मारने के लिए बहू के चाकू उठाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि देवर के हमले के प्रयास की वीडियो बनाने पर बहू ने उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। यह भी आरोप है कि बहू के सहकर्मी से संबंध हैं। जिस कारण वह चार माह पहले गहने, नकदी लेकर फरार हो गई थी। ससुर ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक कॉलोनी निवासी बुजुर्ग ने बताया कि उनकी बड़ी बहू के सहकर्मी से संबंध हैं। जिसकी जानकारी के बाद से बेटे और पत्नी के बीच पांच माह से विवाद चल रहा है। 16 फरवरी को बहू के प्रेमी ने घर आकर बेटे से गाली-गलौज मारपीट की थी। उनके बेटे ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद 26 मई को बहू घर से नकदी, गहने, कपड़े लेकर चली गई थी। उसके मायके वालों को उसकी जानकारी नहीं थी। बेटे ने गाजियाबाद कोर्ट में वाद दायर कराया था। साथ ही थाने को पत्नी के चले जाने की जानकारी दी थी। 12 सितंबर को बहू ने बेटे के पास फोन किया। 13 सितंबर को दोपहर करीब ढाई बजे वह बहू घर पहुंची। उसने बेटे से गाली गलौज करते हुए मारपीट की।

तीन वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, छह सदस्य काबू

फरीदाबाद,एजेंसी। फरीदाबाद पुलिस की एवीटीएस सिकरोना ने गुरुवार को वाहन चोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाले तीन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गैंग के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है, इसके अलावा अन्य कुछ आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार टीम ने सितंबर माह में 14 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 चोरीशुदा वाहन बरामद किए हैं। बरामद वाहनों में एक रॉयल एनफील्ड बुलेट और 19 मोटरसाइकिल शामिल हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त अपराध अमन यादव ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेस के दौरान बताया कि एवीटीएस सिकरोना की टीम ने वाहन चोरी में सक्रिय अलाउदीन-फरीद गैंग, आसिफ-मोहित गैंग तथा आसिफ-हाकम गैंग पर प्रहार करते हुए गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, इन गैंग से जुड़े आरोपितों से चोरी के वाहनों की बरामदगी की गई है। उन्होंने बताया कि आसिफ- मोहित गैंग से दो , मुस्तकीम उर्फ मऊ-हाकम गैंग से चार और अलाउदीन-फरीद गैंग से दो मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। अलाउदीन-फरीद जेल में बंद हैं। उन्होंने बताया कि आसिफ-मोहित गैंग से आसिफ निवासी धौज व मोहित शर्मा निवासी राजस्थान मुस्तकीम गैंग से मुस्तकीम पुत्र महमूद, निवासी गांव धौज, हाकम निवासी नूंह, अलाउदीन-फरीद गैंग से अलाउदीन निवासी दिल्ली तथा फरीद निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि टीम ने उपरोक्त गैंग के अलावा अन्य आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर 12 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इस प्रकार सितंबर माह में विशेष अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए एवीटीएस सिकरोना की टीम ने 20 चोरी के वाहन बरामद किये हैं।

टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर चोरी के अन्य वाहनों की बरामदगी तथा इस नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ पहले भी चोरी सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। बरामद वाहनों का संबंध फरीदाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज वाहन चोरी के मुकदमों से पाया गया है। इनमें थाना सेंट्रल, सेक्टर-17, सेक्टर-58, शहर बल्लभगढ़, मुजेसर, सेक्टर-कोतवाली, सूरजकुंड, कोतवाली तथा खेड़ी पुल क्षेत्र में दर्ज मामले शामिल हैं। कुछ वाहन 2022 और 2023 में दर्ज पुराने मामलों से संबंधित हैं, जबकि कई वाहन वर्ष 2025 और 2026 में दर्ज वाहन चोरी के मुकदमों से जुड़े हैं। पुलिस द्वारा बरामद वाहनों को संबंधित मुकदमों से जोडकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एसआईआर पर चुनाव आयुक्तों में असहमति वोट चोरी का सबूत: पंकज डावर

गुरुग्राम। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने चुनाव आयोग में एसआईआर को लेकर आयुक्तों के बीच सामने आई असहमति को लेकर बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आयोग के अंदर का यह मतभेद सीधे-सीधे वोट चोरी की ओर इशारा करता है। पंकज डावर ने कहा कि नए वोटरों को जोडने और वोटर लिस्ट से नाम हटाने जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर चुनाव आयोग के आयुक्तों को ही अंधेरे में रखा गया। यह जानकारी जब सामने आई तो यह आयोग के अंदर गंभीर विवाद का विषय बन गई। यदि एक संवैधानिक संस्था के अंदर ही पारदर्शिता नहीं होगी तो आम जनता चुनावी निष्पक्षता पर कैसे भरोसा करेगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भाजपा हमेशा दूसरों को हराने के बड़े-बड़े दावे करती है, वही आज एसआईआर के मुद्दे पर अपनी खाल बचाती नजर आ रही है। बंगाल चुनाव पर भाजपा यह कहकर अपना बचाव कर रही है कि जहां वोट कटे हैं, वहां टीएमसी जीती है। भाजपा का यह तर्क उसकी खीझ और बौखलाहट को साफ दिखाता है। जब भाजपा के नेता ऐसे बयान देने को मजबूर हो गए हैं, तो यह साबित होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। पंकज डावर ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा देश के सामने उठाया था, भाजपा तब से लगातार उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भाजपा कभी नए मुद्दे लाकर, कभी बयानबाजी करके असली सवाल को टालने में लगी है। लेकिन अब चुनाव आयोग के भीतर से ही जो असहमति की बात सामने आ रही है, उसने राहुल गांधी के आरोपों पर मुहर लगा दी है।

गुरुग्राम: 61वें वर्ष में श्रीदुर्गा रामलीला का प्रवेश, भव्य मंचन की हो रही तैयारियां

गुरुग्राम। शहर की पुरानी और एनसीआर की प्रसिद्ध रामलीलाओं में शुमार श्री दुर्गा रामलीला कमेटी, जैकबपुरा, गुरुग्राम की इस वर्ष की रामलीला की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ हो गया है। कमेटी की ओर से गुरुवार को रामलीला मैदान में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन किया गया और इसके साथ ही भव्य मंच निर्माण का कार्य शुरू हो गया। इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारी, कलाकार और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

कमेटी के प्रधान लवली सलूजा ने बताया कि श्री दुर्गा रामलीला इस वर्ष अपने 61वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार रामलीला को पहले से अधिक भव्य और दिव्य बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार मंच को भी विशाल और आकर्षक रूप दिया जाएगा। रामलीला का मंचन नई भव्यता और आधुनिक तकनीक के साथ किया जाएगा। लवली सलूजा ने कहा कि कमेटी का प्रयास है कि इस वर्ष दर्शकों को कुछ नया और अलग देखने को मिले। रामलीला को अलग अंदाज, अलग साज और सिनेमेटिक प्रस्तुति के साथ दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। अत्याधुनिक लाइटिंग, एलईडी स्क्रीन, भव्य सेट और दमदार साउंड सिस्टम के माध्यम से दर्शकों को त्रेतायुग की अनुभूति कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार रामलीला में स्थानीय प्रतिभाओं के साथ प्रोफेशनल कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। रामलीला के मीडिया प्रभारी राज सैनी बिसरवाल ने बताया कि इस बार की रामलीला में तकनीक और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। एक ओर पारंपरिक संवाद, भजन और धार्मिक प्रसंग होंगे, वहीं दूसरी ओर सिनेमेटिक दृश्य, विशेष लाइटिंग और धुएं के प्रभाव के माध्यम से समुद्र मंथन, लंका दहन और रावण वध जैसे प्रसंगों को अधिक जीवंत और प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाएगा। कमेटी के प्रबंधन, संरक्षक, सदस्यों ने बताया कि रामलीला के दौरान सुरक्षा और दर्शकों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पूरे रामलीला परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी।

अग्निकांड ने खोले बस माफियाओं के राज: रजिस्ट्रेशन इस राज्य से तो संचालन उस राज्य से, प्रदूषण और फिटनेस कहीं और से

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। थाना जेवर क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार की मध्य रात्रि को डबल डेकर बस में लगी आग और इस घटना में नौ लोगों की हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के दौरान नोएडा पुलिस को पता चला है कि यह बस कश्मीरी गेट से चली थी। तथा उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा जा रही थी। पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि बस मध्य प्रदेश से संचालित होने वाली राजकल्पना ट्रेवल्स की है। यह बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा के लिए जा रही थी। इस बस का पंजीकरण बिहार प्रांत में हुआ है। उन्होंने बताया कि बस का फिटनेस प्रमाण पत्र राजस्थान से, जब की प्रदूषण प्रमाण पत्र हरियाणा से जारी हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बस का नोएडा में कोई स्टॉपेज नहीं था। उन्होंने बताया कि आग बस में लगे एयर कंडीशन में हुए स्पार्क के चलते लगी है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना के बाद पुलिस के अधिकारी रात से सुबह तक घटनास्थल पर मौजूद रहे, तथा गंभीर रूप से झुलसे लोगों को बस से निकालकर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। लेकिन उनकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि नोएडा पुलिस दिल्ली पुलिस को इस आशय का पत्र लिख रही है कि कश्मीरी गेट से अवैध रूप से इतनी बसें कैसे संचालित हो रही हैं। मालूम होगी से पूर्व मे भी 4 अगस्त को कश्मीरी गेट से चलने वाली एक डबल डेकर बस में एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। यह बस नोएडा में रिपेयरिंग के लिए आई थी, तथा परी चौक से युवती सवारी के रूप में उसमें बैठ गई थी। इस मामले में कश्मीरी गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तब भी डबल डेकर बसें चर्चा में आई थी। इसके बाद नोएडा पुलिस ने भी बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की और दर्जनों बसों को सीज किया। इस घटना ने यह जाहिर कर दिया है कि बस माफिया सफेद पोश लोगों से सांठ- गांठ कर इस अवैध कारोबार को चला रहे हैं। यात्रियों ने बताया है कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से रोजाना सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से डबल डेकर बसें संचालित हो रही हैं। मालूम हो कि बुधवार-गुरुवार की मध्य रात को यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग के चलते नौ लोगों की मौत हो गई थी। बस में 35 लोग सवार थे। पुलिस ने 26 लोगों को बाहर निकाल कर उनकी जान बचाई। नौ लोगों की दुखद मौत हो गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख तथा घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है।

पराली प्रबंधन को लेकर नूंह प्रशासन सतर्क

नूंह,एजेंसी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में धान फसल अवशेष प्रबंधन एवं पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों ने भाग लिया। नूंह से उपायुक्त अखिल पिलानी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने जिलों में पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए की जा रही तैयारियों, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की उपलब्धता, किसानों को जागरूक करने के प्रयासों और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पराली जलाने की किसी भी घटना को गंभीरता से लिया जाए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त अखिल पिलानी ने मुख्य सचिव को बताया कि नूंह जिले में पराली प्रबंधन को लेकर व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों, ग्राम स्तर के नोडल अधिकारियों तथा संबंधित विभागों की टीमों को सक्रिय किया गया है, ताकि खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध कृषि मशीनरी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। किसानों को सरकार की ओर से दी जा रही प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। गांव स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। पुलिस, कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखेंगी। देर शाम और रात्रि के समय भी विशेष गश्त की व्यवस्था की जा रही है, ताकि फसल अवशेष जलाने की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण के साथ मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसानों से अपील है कि वे फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें और पराली जलाने से बचें। जिला प्रशासन किसानों के सहयोग से पराली मुक्त नूंह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में पराली की गांठों के सुरक्षित भंडारण, कृषि मशीनरी के समुचित उपयोग, ड्रोन के माध्यम से निगरानी, ग्राम स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती तथा पराली जलाने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

दरवाजा ठीक से बंद न होना पड़ा भारी, घर में घुसे चोर नकदी

साहिबाबाद,एजेंसी। टीला मोड़ थाना क्षेत्र की ईस्ट तुलसी निकेतन कालोनी में रात के समय दरवाजा सही बंद न होने पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से गहने, नकदी और दो मोबाइल चुराकर ले गए। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। ईस्ट तुलसी निकेतन कालोनी निवासी योगेश त्यागी ने बताया कि 22 सितंबर को रात करीब 10 बजे वह घर का गेट बंद कर सो गए। उन्होंने बताया कि किसी कारण दरवाजा सही से बंद नहीं हो सका। जिसका फायदा उठाकर देर रात चोरों ने घर के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह करीब पौने चार बजे बेटी प्रियंका उठी तो उसने देखा कि अलमारी खुली पड़ी है। सामान का सारा बिखरा पड़ा है। बेटी ने उन्हें और अन्य स्वजन को जगाया। जिसके बाद सभी को चोरी की वारदात का पता चला। उन्होंने बताया कि चोर एक जोड़ी चांदी की पायल, एक घड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, 2400 रुपये की नकदी, चार पर्स और दो मोबाइल चुराकर ले गए।

27 सितंबर से पहले निपटा लें सभी जरूरी बैंकिंग कार्य : उपायुक्त

नूंह। उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि आगामी दिनों में संभावित बैंकिंग अवकाश और प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए अपने सभी जरूरी बैंकिंग कार्य समय रहते पूरे कर लें। उन्होंने कहा कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना है, जिससे आमजन, व्यापारी, किसान, कर्मचारी और अन्य बैंक उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है। उपायुक्त ने बताया कि 27 सितंबर को चौथा शनिवार और 28 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक सामान्य रूप से बंद रहेंगे। इसके बाद बैंक यूनियनों की ओर से 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के आह्वान के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में नागरिकों को अपने आवश्यक वित्तीय कार्यों की पहले से योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने के बाद 1 अक्टूबर को इसके अगले दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के राष्ट्रीय अवकाश के कारण बैंक दोबारा बंद रहेंगे। ऐसे में अंतिम समय तक बैंकिंग कार्य टालने से लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अखिल पिलानी ने नागरिकों से आग्रह किया कि नकदी की आवश्यकता, चेक जमा कराने, ड्राफ्ट बनवाने, ऋण से संबंधित कार्य और अन्य जरूरी बैंकिंग लेन-देन 27 सितंबर से पहले ही निपटा लें। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं, यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का अधिक से अधिक उपयोग कर लोग अपनी दैनिक वित्तीय आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पूरा कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि समय रहते आवश्यक तैयारियां कर लेने से नागरिक बैंक शाखाओं में होने वाली भीड़, लंबी प्रतीक्षा और संभावित असुविधा से बच सकते हैं। उन्होंने सभी बैंक उपभोक्ताओं से अपने वित्तीय कार्यों की पूर्व योजना बनाने और संभावित व्यवधान को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने की अपील की।

अपनी रसोई रेस्टोरेंट पर 25 हजार व इनफिनिटी ग्लैम का 10 हजार का चालान

गुरुग्राम,एजेंसी। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ नागरिक सहभागिता पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में चालान कार्रवाई, जन-जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान चलाए गए। नगर निगम की ओर से ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स स्थित अपनी रसोई रेस्टोरेंट के विरुद्ध कचरा फैलाने के मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नगर निगम द्वारा नागरिकों एवं प्रतिष्ठानों से कचरे का जिम्मेदारीपूर्वक निस्तारण करने तथा शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है। टीम द्वारा एक अन्य कार्रवाई करते हुए झाड़सा रोड स्थित ओइन्फिनिटी ग्लैम पर भी कचरा फैलाने के मामले में 10 रुपये रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम द्वारा प्रतिष्ठानों एवं नागरिकों से अपील की गई कि वे कचरे को सार्वजनिक स्थानों पर न डालें तथा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उसका उचित निस्तारण करें। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त यश जालुका ने पार्षद आशीष गुप्ता के साथ सदर बाजार क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से बातचीत कर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली।अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकानों के सामने सडक़ पर कूड़ा न डालें और न ही कूड़ा जमा होने दें। दुकानदारों से नगर निगम की सफाई व्यवस्था में सहयोग करने तथा सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। सेवा ही संकल्प के तहत वार्ड नंबर 34 में शनि मंदिर के आसपास तथा दौलताबाद फ्लाईओवर चौक पर निगम पार्षद सुरेखा चौहान व नागरिकों की सहभागिता से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में वार्ड 22 में भी पार्षद विकास यादव व नागरिकों की सहभागिता से स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया तथा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फैलाने की अपील की गई।

नूंह में एक अक्टूबर से शुरू होगी धान व बाजरा की खरीद

नूंह,एजेंसी। आगामी खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के तहत जिले में धान एवं बाजरा की खरीद एक अक्टूबर से शुरू होगी। खरीद व्यवस्थाओं को लेकर उपायुक्त अखिल पिलानी की अध्यक्षता में वीरवार को लघु सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान एवं बाजरा खरीद शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडियों और खरीद केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, सफाई, हेल्प डेस्क, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में धान की पिछले तीन वर्षों की औसत पैदावार, गैर-बासमती धान के क्षेत्र सत्यापन, बायोमेट्रिक एवं आइरिस उपकरणों की उपलब्धता, नमी मापक यंत्र, वे-ब्रिज, तौल कांटों की कैलिब्रेशन, सीसीटीवी कैमरे, इंटरनेट कनेक्टिविटी और फसल उठान व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त अखिल पिलानी ने किसानों से अपील की कि वे अपनी धान की फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी में लेकर आएं। उन्होंने कहा कि धान में नमी की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। अधिक नमी वाली फसल की खरीद में परेशानी हो सकती है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से कम रखने का प्रयास करें, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की व्यवस्था करने के साथ-साथ तिरपाल, लकड़ी के क्रेट, सफाई सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडियों में पहुंचने वाली फसल का नियमित रूप से उठान किया जाए, ताकि मंडियों में अनावश्यक भीड़ न हो और किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर एसडीएम फिरोजपुर झिरका रूहानी, एसडीएम पुन्हाना अमित गुलिया, एसडीएम तावडू जितेंद्र कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा डीएफएससी सीमा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

वन्देमातरम् बनाम धर्मनिरपेक्षता की आड़ में भारत को बर्बाद करने का षड्यंत्र!

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

वंदेमातरम् को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई ने भारत की धर्मनिरपेक्षता की उस बहस को फिर सामने ला दिया है, जिसे अक्सर सुविधा के अनुसार अलग-अलग अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति वंदेमातरम् गाए या न गाए। प्रश्न यह है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? क्या धर्मनिरपेक्षता अकेले धार्मिक असहमति के अधिकार की रक्षा करती है या फिर राज्य की नीतियों में सभी धार्मिक समुदायों के साथ समान संवैधानिक व्यवहार की मांग भी करती है? जब किसी राष्ट्र की मूल चेतना और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों पर ही सवाल खड़े किए जाने लगें, तो नागरिकों के एक बड़े वर्ग में यह संशय गहराने लगता है कि क्या धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल देश को वैचारिक रूप से बांटने के लिए किया जा रहा है? 22 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक संगीतकार टी.एम. कृष्णा की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में 2026 में किए गए उस संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से वंदेमातरम् को राष्ट्रगान के समान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून के दायरे में लाया गया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संकेत दिया कि धार्मिक अथवा वास्तविक अंतरात्मा संबंधी आपत्ति के कारण वंदेमातरम् न गाने वाले व्यक्ति को आपराधिक परिणाम नहीं भुगतने चाहिए और 1986 के बिजो इमैनुएल निर्णय में स्थापित सिद्धांत लागू रहेंगे। वस्तुतः इस कानूनी लड़ाई ने एक बार फिर राष्ट्रीय अस्मिता को न्यायालय के कटघरे में खड़ा कर दिया है, विचार करें कि क्या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर होना चाहिए? वास्तव में वंदेमातरम् की संवैधानिक और राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करते समय 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की कार्यवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा और स्वतंत्रता संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदेमातरम् को उसके समान सम्मान और समान दर्जा दिया जाएगा। संविधान सभा की मूल कार्यवाही इसका आधिकारिक प्रमाण है। नए कानूनी आधिकारिक तथ्य-पत्र में भी वंदेमातरम् के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया गया है। यह गीत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा था, 1875 में प्रकाशित हुआ और बाद में आनंदमठ में शामिल हुआ। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ ठाकुर ने इसे संगीतबद्ध कर गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में यह राष्ट्रीय प्रतिरोध के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में सामने आया। इसका इतना श्रेष्ठ इतिहास होने की स्थिति में वंदेमातरम् को बिल्कुल भी धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित करने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने तथा कानून के अनुसार संपत्ति रखने और उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार या संरक्षण के लिए विशेष रूप से लगाए गए कर के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म को मिटाने की व्यवस्था नहीं है।

यह राज्य को किसी विशेष धर्म का पक्षकार बनने से रोकते हुए नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, इसलिए जब वंदेमातरम् के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी जाती है तो यही कसौटी अन्य मामलों में भी लागू होनी चाहिए। यदि किसी धार्मिक समुदाय की आस्था, संस्था या संपत्ति से जुड़ा प्रश्न उठता है तो निर्णय समान संवैधानिक सिद्धांतों, कानून और पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए। आज क्या यह भारत में समानता के आधार पर कहीं होता दिख रहा है? यहीं हिंदू समाज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धार्मिक संस्थाओं के मामलों में राज्य की समान और निष्पक्ष भूमिका है तो मंदिरों, वक्फ संपत्तियों, चर्च संस्थाओं और अन्य धार्मिक न्यासों से जुड़े प्रशासन और संपत्ति संबंधी प्रश्नों पर भी समान संवैधानिक कसौटी लागू होनी चाहिए। वह अब तक क्यों नहीं की गई है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए कि धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन में राज्य की भूमिका का आधार सभी समुदायों के लिए समान क्यों नहीं रखा गया है? यही बात मदरसा, चर्च या मिशनरी संस्थाओं की संपत्ति पर भी लागू होती है। क्यों उन्हें छूट दी गई है? क्यों वक्फ बोर्ड बनाया गया है? वे भारत में हलाल सर्टिफिकेट कैसे चला सकते हैं? इसी प्रकार अल्पसंख्यक आयोग या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आखिर भारत में कर क्या रहे हैं? जब सभी धर्म समान होने चाहिए, राज्य की नजर में, फिर यह धर्मनिरपेक्षता की आड़ लेकर क्यों इन पर बहुसंख्यक हिन्दू समाज का धन इन अल्पसंख्यक संस्थानों पर खर्च किया जा रहा है? जिसमें कि फिर संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक अधिकारों तथा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने के अधिकार की रक्षा करने की जो दुहाई अक्सर दी जाती है, वह भी बंद होना चाहिए। क्योंकि देश के प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार है, इसलिए वह अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक नहीं हो सकती है, पर व्यवहार में क्या हो रहा है, वह आज सामने है। अल्पसंख्यक स्कूल, कॉलेज उनकी अपनी व्यवस्था जिसमें कि वे आरटीई के बच्चों के प्रवेश भी नहीं लेते हैं! क्या यही चयनित धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए? जिसमें सिर्फ बहुसंख्यक होने के कारण से उस समाज के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा! अरे, जन्म लेनेवाले बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि वह कहां जन्म ले रहा है, लेकिन यहां तो बहुसंख्यक समाज में जन्म लेने के कारण वह उन तमाम सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है जोकि एक राज्य के नागरिक के रूप में उसके अन्य किसी दूसरे नागरिक के समान ही बराबर के अधिकार होने चाहिए थे। ऐसे में जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वन्देमातरम् का विरोध कर रहे हैं, फिर तो उनके लिए भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वर्तमान में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों को अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में लेकर विभिन्न योजनाएं संचालित करता है, इस व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन में हिंदू परंपरा की ऐतिहासिक भूमिका को आज संपूर्ण विश्व स्वीकार्य कर रहा है।

भारत की सांस्कृतिक विरासत में हिंदू दर्शन, परंपराओं, तीर्थों, साहित्य, कला और सामाजिक संस्थाओं का अत्यंत व्यापक योगदान है, इसलिए हिंदू समाज के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा और अन्य समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करना समस्या का समाधान नहीं है। समानता का अर्थ यही है कि बहुसंख्यक नागरिक के अधिकार भी उतने ही वास्तविक माने जाएं जितने अल्पसंख्यक नागरिक के भारत में 1950 से संविधान लागू होने के समय से माने जा रहे हैं। वस्तुतः जब नीति-निर्माता सिर्फ एक वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के प्रति अति-संवेदनशील दिखाई देते हैं और बहुसंख्यक समाज की ऐतिहासिक धरोहर व उसके मौलिक नागरिक अधिकारों की बात पर मौन साध लेते हैं, तब सामाजिक असंतोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसे में कहना यही है कि वंदेमातरम् के नाम पर धर्मनिरपेक्षता को चयनात्मक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यदि धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है तो वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और हर दूसरे नागरिक के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान आवश्यक है तो उसकी अपेक्षा भी सभी से समान होनी चाहिए। यदि धार्मिक संस्थाओं को कानून के अनुसार अपने मामलों का संचालन करने का अधिकार है तो राज्य का नियमन भी समान संवैधानिक कसौटी पर होना चाहिए। भारत को किसी एक समुदाय की धार्मिक श्रेष्ठता या किसी दूसरे समुदाय की राजनीतिक विशेषाधिकार व्यवस्था से नहीं चलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जोर समान नागरिक अधिकारों और समान कानून से मजबूती पर होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता यदि वास्तव में संविधान का मूल्य है तो उसे आधी-अधूरी सुविधा के रूप में नहीं, पूर्ण संवैधानिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना सभी के लिए समान रूप से अनिवार्य है। किसी नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, किसी समुदाय के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न हो और साथ ही राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान तथा कानून के शासन की रक्षा हो, यही वह संतुलन है जिसकी भारत जैसे बहुधार्मिक लोकतंत्र को आवश्यकता है। इसमें कोई हिन्दू, मुस्लिम या अन्य मत, पंथ, रिलीजन, धर्म की बात नहीं है। इतना तो काश, वन्देमातरम् का विरोध कर रहे भारत के नागरिक समझ ही सकते हैं!

भारत में आज की दूरसंचार यात्रा शानदार तकनीकी प्रगति और सामूहिक जिम्मेदारी, दोनों का अनूठा संगम नजर आता है। दूरसंचार विभाग के जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या 1,204.01 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। सब्सक्राइबरों की यह विशाल संख्या भारत के जुड़े हुए डिजिटल इकोसिस्टम के व्यापक दायरे को दर्शाती है। देश में लागू मजबूत कानूनी प्रावधान, उन्नत सरकारी वेरिफिकेशन टूल्स (जैसे संचार साथी और डिवाइस सेतु) और नागरिकों के बीच बढ़ती हुई तकनीकी जागरूकता मिलकर हमारे डिजिटल नेटवर्क को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। इस डिजिटल भरोसे को बनाए रखने में सरकार, उद्योग जगत और आम यूजर्स प्रत्येक हितधारक की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक जागरूक, सतर्क और हर नियम से वाकिफ नागरिक ही किसी भी प्रकार के डिजिटल फ्रॉड और तकनीकी छेड़छाड़ के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच साबित होता है। सरकार और समाज के निरंतर आपसी सहयोग से ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी पूरी तरह सुरक्षित, संप्रभु और मजबूत बनी रहेगी। देश में तीव्र डिजिटल विस्तार अपने साथ सुरक्षा से जुड़ी कई नई और जटिल चुनौतियां भी लेकर आया है।

क्या कड़े प्रावधान से डिजिटल फ्रॉड पर लगेगा अंकुश?

ओ.पी. पाल

भारत में तेजी से हो रहे डिजिटल बदलाव ने दूरसंचार उपकरणों, खासतौर से मोबाइल इंसान के लिए रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और शासन (गवर्नेंस) का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया है। आज हमारे मोबाइल नेटवर्क और डिवाइस डिजिटल पेमेंट, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं और नागरिकों पर केंद्रित विभिन्न डिजिटल पहलों को सीधे तौर पर समर्थन दे रहे हैं। जैसे-जैसे इन तकनीकों पर देश की निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे ही हमारे दूरसंचार नेटवर्क और डिवाइस की सुरक्षा और अखंडता (इंटीग्रिटी) को कायम रखना भी बड़ी चुनौती है, जिसमें साइबर अपराध यानी डिजिटल फ्रॉड ने बड़े पैमाने पर पांव पसार रखे हैं। हालांकि भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार का संचार साथी प्लेटफॉर्म एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रहा है लेकिन डिजिटल फ्रॉड का दायरा भी कम नहीं हुआ है। शायद इसी चुनौती का मुकाबला करने की दिशा में भारत सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत दूरसंचार उपकरणों मोबाइल हैंडसेट और अन्य टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के आईएमईआई नंबर के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ नियमों को अत्यंत सख्त करते हुए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अब सवाल यही है कि क्या भारत सरकार द्वारा सख्त किये गये नियमों और प्रावधानों से देश में डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लग पाएगी?

भारत में आज की दूरसंचार यात्रा शानदार तकनीकी प्रगति और सामूहिक जिम्मेदारी, दोनों का अनूठा संगम नजर आता है। दूरसंचार विभाग के जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या 1,204.01 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। सब्सक्राइबरों की यह विशाल संख्या भारत के जुड़े हुए डिजिटल इकोसिस्टम के व्यापक दायरे को दर्शाती है। देश में लागू मजबूत कानूनी प्रावधान, उन्नत सरकारी वेरिफिकेशन टूल्स (जैसे संचार साथी और डिवाइस सेतु) और नागरिकों के बीच बढ़ती हुई तकनीकी जागरूकता मिलकर हमारे डिजिटल नेटवर्क को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। इस डिजिटल भरोसे को बनाए रखने में सरकार, उद्योग जगत और आम यूजर्स प्रत्येक हितधारक की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक जागरूक, सतर्क और हर नियम से वाकिफ नागरिक ही किसी भी प्रकार के डिजिटल फ्रॉड और तकनीकी छेड़छाड़ के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच साबित होता है। सरकार और समाज के निरंतर आपसी सहयोग से ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी पूरी तरह सुरक्षित, संप्रभु और मजबूत बनी रहेगी। देश में तीव्र डिजिटल विस्तार अपने साथ सुरक्षा से जुड़ी कई नई और जटिल चुनौतियां भी लेकर आया है। इनमें से एक सबसे गंभीर चिंता इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई) नंबर के गलत इस्तेमाल या उससे छेड़छाड़ से जुड़ी है, जिसकी वजह साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। आईएमईआई नंबर के साथ छेड़छाड़ या उसके अनधिकृत संशोधन के कारण बदली हुई पहचान वाले उपकरणों का इस्तेमाल आसान हो जाता है, जिससे दूरसंचार नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस की असली पहचान करना बेहद कठिन हो जाता है। इस तरह की हरकतें कानून लागू करने वाली एजेंसियों, उपभोक्ता सुरक्षा और समग्र राष्ट्रीय नेटवर्क सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं। इसलिए, एक सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत दूरसंचार इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए डिवाइस आइडेंटिफायर (पहचानकर्ताओं) की अखंडता को मजबूत करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। टेलीकॉम नेटवर्क की भाषा आईएमईआई की तकनीकी बनावट और इसकी कार्यप्रणाली को समझना हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। आईएमईआई एक विशिष्ट 15 अंकों का नंबर होता है जो दुनिया भर के दूरसंचार नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल डिवाइस की अनूठी पहचान करता है। आईएमईआई नंबर के शुरुआती आठ अंक 'टाइप एलोकेशन कोड' (टीएसी) बनाते हैं, जो सीधे तौर पर डिवाइस के मॉडल या उसके विशेष प्रकार की पहचान करते हैं। 'ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन' (जीएसएमए) टीएसी के वैश्विक आवंटन (एलोकेशन) की देखरेख करता है।

जीएसएमए निर्माताओं और ब्रांड मालिकों को टीएसी जारी करता है, जिसके बाद विनिर्माता प्रत्येक डिवाइस को अलग और विशिष्ट आईएमईआई नंबर आवंटित करते हैं। आज के दौर में चलन में मौजूद डुअल-सिम फोन में आमतौर पर दो अलग-अलग आईएमईआई नंबर होते हैं यानी प्रत्येक सिम स्लॉट के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या है। भारत में बनने वाले सभी संबंधित दूरसंचार उपकरणों के आईएमईआई नंबरों को पहली बार बाजार में बेचने, उनकी टेस्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर एंड डी) या अन्य किसी भी उपयोग से पहले सरकार के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मोबाइल डिवाइस इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (आईएमईआई) को हटाना, मिटाना या उसमें बदलाव करने का प्रयास करता है या फिर जानबूझकर ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, निर्माण करना, उसकी तस्करी करना या उस पर नियंत्रण रखना, जिसके बारे में उसे यह ज्ञात हो कि उसका उपयोग आईएमईआई से छेड़छाड़ के लिए किया जाएगा, तो उसे उसे गंभीर अपराध माना जाएगा। छेड़छाड़ किए गए या कॉन्फ़िगर किए जा सकने वाले आईएमईआई वाले उपकरणों को बेचना या उनका व्यापार करना सीधे तौर पर गंभीर कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करता है। भारत सरकार ने दूरसंचार इकोसिस्टम की पवित्रता, सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक अत्यंत मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 में मोबाइल हैंडसेट और अन्य टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जैसे दूरसंचार उपकरणों के आईएमईआई नंबर के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ नियमों को सख्त करने के साथ अत्यंत सख्त और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। मसलन इन प्रावधानों में धारा 42(3)(सी) के तहत किसी भी रूप में टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर्स के साथ छेड़छाड़ करने पर पूरी तरह रोक लगाती है। वहीं धारा 42(3)(ई): यह धारा धोखाधड़ी, जालसाजी या किसी अन्य व्यक्ति का रूप धरकर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (सिम) या टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर्स हासिल करने पर प्रतिबंध लगाती है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के लिए तीन साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। वहीं एक्ट की धारा 42(7) के अंतर्गत इस श्रेणी के सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार धारा 42(6) के तहत जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे गंभीर अपराधों को करने में मदद, समर्थन या बढ़ावा देते हैं, उन्हें भी मुख्य अपराधियों की तरह ही समान रूप से दंडित किया जाएगा। यह मजबूत विधिक ढांचा देशभर में आईएमईआई से छेड़छाड़ और दूरसंचार संसाधनों के हर तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बेहद प्रभावी और निवारक उपाय साबित हो सकता है। भारत में किसी भी प्रकार के संबंधित दूरसंचार उपकरणों का आयात करने से पहले आयातकों को केंद्र सरकार के पास उनके आईएमईआई नंबर पंजीकृत कराने होंगे। बिक्री, टेस्टिंग या आरएंडडी के लिए लाए जाने वाले उपकरणों का पंजीकरण भी 'डिवाइस सेतु-आईसीडीआर' पोर्टल के जरिए ही पूरा किया जाना आवश्यक है। वहीं आयातकों को यह सत्यापित करना होगा कि आयातित उपकरणों पर केवल वैध और अधिकृत आईएमईआई नंबर ही मौजूद निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक डिवाइस को सही, विशिष्ट और छेड़छाड़-मुक्त आईएमईआई नंबर ही आवंटित किए जाएं। ब्रांड मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने वाले सभी उपकरण आईएमईआई पंजीकरण और नवीनतम साइबर सुरक्षा से जुड़ी सभी अनिवार्य शर्तों को पूरी तरह पूरा करते हों।

विचार

नकली व बेलगाम दवाओं के खिलाफ अब अदालत का ही आसरा

अशोक भाटिया

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जहां जन-कल्याण को शासन का मूलमंत्र माना जाता है, वहां स्वास्थ्य का क्षेत्र एक गंभीर संक्रमण काल से गुजर रहा है। बीमारियां जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से चिकित्सा के नाम पर इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ का एक भयावह और अनैतिक तंत्र विकसित हो चुका है। हाल ही में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में मुनाफे की हवस और मरीजों के साथ हो रही धोखाधड़ी की गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनाई दी है। न्याय के सर्वोच्च मंदिर ने दवा निर्माताओं, अस्पतालों और सरकारी नियामक संस्थाओं के रवैये पर जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, उसने हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रयुक्त यह वाक्य— 'यह तो सीधे तौर पर दिन-दहाड़े डकैती है '—महज एक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस लाचार भारतीय नागरिक की सामूहिक चीख का प्रतिनिधित्व करता है, जो बीमारी से पहले इलाज के खर्च और उसमें होने वाली जालसाजी से मर जाता है। न्यायालय के समक्ष जो तथ्य उभरकर सामने आए हैं, वे किसी भी संवेदनशील समाज को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। खासकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों के घावों पर जिस तरह मुनाफाखोरी का नमक छिड़का जा रहा है, वह अमानवीयता की पराकाष्ठा है। अदालत के संज्ञान में लाया गया कि कैंसर की एक आवश्यक जीवन रक्षक दवा, जिसकी कीमत निर्माता कंपनी द्वारा रिटेलर के लिए महज ?2,700 तय की जाती है, उस पर अधिकतम खुदरा मूल्य पूरे ?27,000 छाप दिया जाता है। यानी कि लागत और थोक मूल्य से ठीक दस गुना अधिक दाम पर उस दवा को बेचे जाने की खुली छूट दे दी गई। एक पीड़ित परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस अकल्पनीय मूल्य अंतर पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने सीधे शब्दों में सवाल पूछा कि मरीजों को इस तरह बेदर्दी से लूटने की इजाजत व्यवस्था कैसे दे सकती है? निर्माता कंपनियां और बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट फार्मेसियां मिलकर मरीजों की जेब पर जो डाका डाल रही हैं, उस पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी नियामक इकाइयां आंखें मूंदकर क्यों बैठी हैं? यह मामला सिर्फ निजी क्षेत्र की लूट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के खजाने और टैक्सपेयर्स के पैसे में सेंधमारी का भी एक बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। आज केंद्र सरकार 'आयुष्मान भारत', ष्टत्र।।स् और ष्टत्र।।स् जैसी लोक-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज का खर्च उठाती है। निजी अस्पताल इन्हीं बढ़ी हुई और मनमानी एमआरपी पर दवाएं खरीदते हैं और बाद में सरकारी खजाने से उसका शत-प्रतिशत रीइम्बर्समेंट क्लेम करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि चंद दवा माफियाओं और निजी अस्पतालों की तिजोरियां भरने के लिए आम जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा है। करदाताओं का पैसा जो देश के बुनियादी ढांचे और लोक-कल्याण में लगना चाहिए था, वह दवा कंपनियों की साठगांठ की भेंट चढ़ रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए इसे 'स्पष्ट रूप से देश और जनता के साथ एक बड़ा फ्रॉड' करार दिया है। इस संदर्भ में एक अहम सुझाव यह भी आया कि क्यों न देश की सभी जीवन रक्षक दवाओं को एक एकीकृत मूल्य-नियंत्रण के दायरे में ला दिया जाए, जिससे जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का यह पूरा कृत्रिम भ्रम ही समाप्त हो जाए और दवाएं समान दाम पर उपलब्ध हो सकें। एक तरफ जहां दवाओं के नाम पर यह संस्थागत और कानूनी लूट जारी है, वहीं दूसरी तरफ 'नकली दवाओं' का एक समानांतर और अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड चल रहा है, जो सीधे मौत का व्यापार कर रहा है। हाल ही में बेंगलुरु में विशेष जांच दल और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी में एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय नकली कैंसर दवा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में जो तथ्य सामने आए, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। वीरेश कुमार जैन नामक एक फार्मासिस्ट की मुख्य संलिप्तता वाले इस गिरोह ने करीब 90 से अधिक प्रतिष्ठित अस्पतालों और क्लीनिकों में पिछले पांच वर्षों से नकली तथा एक्सपायर्ड हो चुकी कैंसर और आईसीयू दवाओं की धड़ल्ले से आपूर्ति की। ये अपराधी एक्सपायर हो चुकी दवाओं को दोबारा प्रोसेस करते थे, उन्हें चमचमाते नए डिब्बों में पैक करते थे, नामचीन अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय फार्मा ब्रांडों के नकली होलोग्राम और लेबल लगाते थे और अस्पतालों के परचेजिंग डिपार्टमेंट को आकर्षित करने के लिए पचास प्रतिशत तक के भारी डिस्काउंट का लालच देते थे। पांच साल तक, यानी कि 1,800 से अधिक दिनों तक अस्पतालों के खरीद तंत्र ने बिना किसी लैब टेस्टिंग या प्रामाणिकता की जांच किए, सिर्फ मुनाफे के लालच में इन नकली दवाओं को खरीदा और उन लाचार मरीजों के जिस्म में कीमोथेरेपी के नाम पर जहर के रूप में उतार दिया जो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर वहां आए थे।

एक नजर

कटिहार रेल मंडल से चलेंगी 18 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें

कटिहार। आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार रेल मंडल ने व्यापक तैयारी की है। यात्रियों की सुगम व आरामदायक आवाजाही के लिए विभिन्न दिशाओं में बड़े पैमाने पर पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसके तहत कटिहार रेल मंडल से 10 जोड़ी तथा मंडल को बाइपास करने वाले मार्गों से 8 जोड़ी, यानी कुल 18 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सीनियर डीसीएम सह पीआरओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पर्व के समय नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) और यात्रियों के अत्यधिक दबाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा यह विशेष कदम उठाया गया है। ये स्पेशल ट्रेनें आनंद विहार (दिल्ली), मुंबई, अमृतसर, यशवंतपुर, गोमतीनगर और भागलपुर सहित देश के कई प्रमुख महानगरों और औद्योगिक शहरों के लिए निर्धारित तिथियों में परिचालित की जाएंगी। विशेष ट्रेनों के चलने से त्योहारी सीजन में महानगरों से अपने घर लौटने वाले परदेसियों और छठ व्रतियों को कन्फर्म सीट पाने में काफी सहूलियत होगी। सीनियर डीसीएम ने आम रेल यात्रियों से अपील की है कि वे पर्व के दौरान इन स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में भीड़भाड़ से बचने के लिए उचित व वैध टिकट लेकर ही सुरक्षित यात्रा करें।

बायसी में आंधी-तूफान का कहर, 50 से अधिक घरों के छप्पर उड़े

पूर्णिया,एजेंसी। जिले में बायसी प्रखंड क्षेत्र के गांगर पंचायत अंतर्गत मालोपारा तेलंगा गांव में गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे अचानक आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज हवा के कारण गांव के 50 से अधिक घरों के छप्पर उड़ गए, जबकि कई घरों में रखा घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक आए तूफान से पूरे गांव में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार दोपहर में मौसम अचानक बदला और देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी। हवा की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई घरों के टीन, फूस और अन्य सामग्री से बने छप्पर उखड़कर दूर जा गिरे। कई परिवारों के घर खुले आसमान के नीचे आ गए। घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन एवं अन्य जरूरी सामान भी तूफान की चपेट में आने से खराब हो गया। घटना के बाद प्रभावित परिवार अपने घरों और सामान को संभालने में जुट गए। कई स्थानों पर टूटे छप्पर और बिखरे सामान के कारण गांव में तबाही का दृश्य दिखाई दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों का शीघ्र सर्वे कराकर सरकारी प्रावधान के तहत सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में बायसी के अंचलाधिकारी गणेश पासवान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही राजस्व कर्मचारी को प्रभावित गांव में जांच के लिए भेज दिया गया है। नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वामन मंदिर और रामरेखा घाट के विकास में तेजी लाने का निर्देश

बक्सर। जिले के प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। गुरुवार को समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक स्थलों पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बक्सर की ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक विरासत को पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने के लिए विकास योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय-सीमा में किया जाना जरूरी है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने के साथ कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में वामन भगवान मंदिर प्रांगण के समग्र विकास एवं कायाकल्प को लेकर विशेष चर्चा हुई। पर्यटन की दृष्टि से मंदिर परिसर को विकसित करने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मंदिर परिसर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया। रामरेखा घाट पर पर्यटक सुविधाओं के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बक्सर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का योजनाबद्ध विकास आवश्यक है। बैठक में पर्यटन विभाग से संबंधित अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया।

बाढ़ प्रबंधन के लिए स्थायी समाधान की दिशा में कार्ययोजना बनाकर काम करना है: मुख्यमंत्री

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज गंगा, गंडक एवं कोसी नदी परियोजना, बक्सर-भागलपुर ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना, 2400 (3×800) मेगावाट पीरपैंती प्लांट तथा पीएम कुसुम योजना से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन को लेकर स्थायी समाधान की दिशा में कार्य योजना बनाकर कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी, कोसी नदी एवं गंडक नदी को व्यवस्थित करना है। इसके दोनों तरफ तटबंधों का मजबूतीकरण करते हुए उस पर फोरलेन सड़क का निर्माण करना है। गंगा नदी, कोसी नदी एवं गंडक नदी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को स्थायी राहत प्रदान करने के साथ-साथ इस क्षेत्र को समृद्ध क्षेत्र बनाना है। कोसी क्षेत्र के शुरूआती 100 किलोमीटर जो विशेष डेंजर जोन है, उस पर डबल शीट पायलिंग करने की आवश्यकता है। नदियों का गाद निकालने से जल संग्रहण एवं प्रवाह क्षमता भी संयमित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संबंधित विभाग परियोजनाओं की नियमित निगरानी, आपसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि राज्य में जल संसाधन, सड़क कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र की आधारभूत संरचना को और मजबूत किया जा सके। कोसी नदी प्रणाली की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोसी एक गतिशील एवं आपस में जुड़ी हुई नदी प्रणाली है। इसके प्रबंधन के लिए केवल वार्षिक बाढ़ प्रतिक्रिया तक सीमित रहने के बजाय दीर्घकालिक बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण की रणनीति के तहत कार्य किया जाए। उन्होंने कोसी क्षेत्र को लोगों, संपत्तियों और कनेक्टिविटी से जुड़े बहु-जिला नदी गलियारे के रूप में देखते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बक्सर भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की प्रगति पर चर्चा हुई। इस परियोजना की कुल लंबाई 348.196 किलोमीटर है, जिसमें 336.205 किलोमीटर बिहार तथा लगभग 12 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है।

मुख्यमंत्री ने इसके अतिरिक्त गंगा-अंबिका पथ (बिदुपुर दिघवारा), नारायणी पथ (दरिहारा-डुमरिया घाट) और विश्वामित्र पथ (बक्सर आरा-मनेर) से संबंधित परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान पीरपैंती तापीय विद्युत परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई।

इस परियोजना की क्षमता 3ङ्ग800 मेगावाट है। इसके साथ ही बांका तापीय विद्युत संयंत्र से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने पीएम-कुसुम योजना के तहत कृषि फीडरों के सोलराइजेशन की प्रगति की जानकारी ली और इसे तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को पर्याप्त एवं भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के साथ-साथ सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने राजकीय नलकूपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया।

राजकीय पॉलिटेक्निक में एम्प्लॉयबिलिटी एन्हांसमेंट प्रोग्राम का समापन एवं प्रमाण-पत्र वितरण

सहरसा। राजकीय पॉलिटेक्निक, सहरसा के अंतिम वर्ष के डिप्लोमा छात्र-छात्राओं के लिए इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड लाइवलीहुड फेज-2 के अंतर्गत आयोजित एम्प्लॉयबिलिटी एन्हांसमेंट प्रोग्राम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में रोजगार के लिए आवश्यक संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास, टीमवर्क, साक्षात्कार कौशल एवं कार्यस्थल से संबंधित व्यवहारिक दक्षताओं का विकास करना था। प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को समारोह में प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य प्रो. मिथुन कुमार ने कहा आज के प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार में तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास एवं व्यावसायिक कौशल अत्यंत आवश्यक हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्र-छात्राओं को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट समन्वयक प्रो. धर्मेंद्र कुमार ने कहा, 'इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं को रोजगार एवं प्लेसमेंट की तैयारी के लिए उपयोगी कौशल प्राप्त हुए हैं। हमारा प्रयास है कि छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के साथ बेहतर रोजगार अवसरों के लिए निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के सह-समन्वयक प्रो. सौरभ ने कहा, 'इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्र-छात्राओं में आत्मविश्वास, संचार क्षमता एवं साक्षात्कार कौशल को विकसित करने में सहायक होते हैं तथा उन्हें रोजगार के लिए बेहतर ढंग से तैयार करते हैं।

कार्यक्रम के प्रशिक्षक श्री राम कृष्ण पांडेय ने छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण के दौरान संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास, टीमवर्क, साक्षात्कार की तैयारी तथा कार्यस्थल पर आवश्यक व्यवहारिक कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के सफल समापन पर छात्र-छात्राओं में उत्साह देखा गया। प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं ने इस प्रशिक्षण को रोजगार एवं भविष्य के व्यावसायिक जीवन के लिए उपयोगी बताया। इस अवसर पर प्रो. मिंटू, प्रो. सिद्धांत, प्रो. लक्ष्मी, प्रो. प्रभास, प्रो. शुभम, प्रो. श्वेता, प्रो. मुकेश सहित संस्थान के अन्य व्याख्याता एवं कर्मचारी तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कोसी तटबंध की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने किया निरीक्षण

सुपौल। कोसी नदी के बढ़ते-घटते जलस्तर को देखते हुए तटबंध की सुरक्षा एवं कटावरोधी सामग्रियों के भंडारण की स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार को अधिकारियों की टीम ने कोसी नदी के पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार, कार्यपालक अभियंता, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित जल संसाधन विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल रहे।

निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता से कटावरोधी सामग्रियों के भंडारण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने तटबंध की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में कटावरोधी सामग्री उपलब्ध रखने के साथ-साथ ट्रैक्टर, जेसीबी एवं अन्य आवश्यक मशीनरी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि तटबंध की सतत निगरानी के लिए विभिन्न स्थानों पर अभियंताओं की तैनाती की गई है। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में मजदूरों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सुरक्षात्मक कार्य शुरू किया जा सके।उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में तटबंध एवं स्पर की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा कई सुरक्षात्मक कार्य कराए गए हैं तथा वर्तमान में भी आवश्यक कार्य जारी हैं। विभाग के अनुसार फिलहाल तटबंध सुरक्षित एवं मजबूत स्थिति में है।

कामकाज में लापरवाही पर एसएसपी का बड़ा एक्शन, लोदीपुर थानाध्यक्ष समेत सभी अधिकारियों का वेतन रोका, विभागीय जांच शुरू

भागलपुर,एजेंसी। जिले के लोदीपुर थाने में पुलिसिंग और रिकॉर्ड संधारण में बरती जा रही घोर लापरवाही पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को लोदीपुर थाने के औचक निरीक्षण के दौरान पुलिस के कामकाज में कई गंभीर कमियां पाई गईं। इसके बाद एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोदीपुर थानाध्यक्ष समेत थाने के सभी पुलिस पदाधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू करने का कड़ा निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि एसएसपी ने गुरुवार को लोदीपुर थाने का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, मालखाना, हाजत, शस्त्रागार, महिला हेल्प डेस्क और सीसीटीवी व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। जब थाने में संधारित विभिन्न महत्वपूर्ण पंजियों और सरकारी अभिलेखों की गहन जांच की गई, तो उनके रखरखाव में भारी लापरवाही उजागर हुई। एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान न सिर्फ व्यवस्था देखी, बल्कि पुलिस के मूल जांच कार्यों की भी समीक्षा की।

श्रम और कर्म के प्रति सम्मान ही समृद्ध समाज की आधारशिला : तारकिशोर प्रसाद

कटिहार,एजेंसी। नगरनिगम के दुर्गा स्थान चौक स्थित जुगत भवन में भगवान श्री बलभद्र पूजन आयोजन समिति के तत्वावधान में कलवार समाज, कटिहार द्वारा भव्य पूजन सह समाज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकजेश उर्फ मुकेश चौधरी ने की, जबकि समारोह का विधिवत उद्घाटन बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सह विधायक तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बलरामपुर विधायक संगीता देवी और बरारी के पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भगवान बलभद्र केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं, बल्कि वे कृषि, श्रम, समृद्धि, अनुशासन और लोक जीवन की गौरवशाली परंपरा के संवाहक हैं। उन्होंने कहा कि उनके हाथों में सुशोभित हल यह संदेश देता है कि धरती, श्रम और कर्म के प्रति सम्मान ही समृद्ध समाज की वास्तविक आधारशिला है। भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र जी का जीवन हमें सामर्थ्य के साथ सरलता, शक्ति के साथ संयम और पराक्रम के साथ लोक कल्याण की प्रेरणा देता है। उनकी आराधना अपनी सांस्कृतिक जड़ों, पूर्वजों की परंपरा और सामाजिक एकता के प्रति सम्मान का पावन संकल्प है। बलरामपुर विधायक संगीता देवी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह मंगलमय आयोजन समाज में एकता, सद्भाव, संस्कार और आपसी प्रेम को और सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों का अनुभव, मातृशक्ति का आशीर्वाद और युवा शक्ति का उत्साह मिलकर समाज को नई ऊर्जा व सही दिशा प्रदान करेगा।

एक नजर

एशियाई खेल : चीन ने लगातार 14वीं बार जीता महिला जिम्नास्टिक टीम स्वर्ण

नागोया (जापान),एजेंसी। चीन ने बुधवार को 2026 एशियाई खेलों में महिला जिम्नास्टिक टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर इस स्पर्धा में लगातार 14वीं बार खिताब अपने नाम किया। चीन ने कुल 166.462 अंक हासिल किए। मेजबान जापान 165.362 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर कोरिया ने 158.329 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। चीन की स्वर्णिम टीम में के चिनचिन, झांग यिहान, दू सियू, झांग छिंगयिंग और छ्यू छियुआन शामिल थीं। इससे पहले चीन की पुरुष जिम्नास्टिक टीम भी टीम स्पर्धा का स्वर्ण जीत चुकी है। मुकाबले की शुरुआत में जापान ने वॉल्ट स्पर्धा में बढ़त बनाई। लैंडिंग में गलती के कारण चीन की के चिनचिन को 12.366 अंक मिले, जबकि जापान की आइको सुगिहारा ने 14.066 अंक हासिल किए। पहली रोटेशन के बाद चीन 1.9 अंक पीछे था। चीन ने असमान बार स्पर्धा में शानदार वापसी की। झांग छिंगयिंग ने 14.033 अंक हासिल किए, जबकि छ्यू के गिरने के बावजूद उनकी कठिनाई का स्कोर 6.3 रहा और उन्हें 14.033 अंक मिले। दू सियू ने 14.866 अंक के साथ रोटेशन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर हासिल कर चीन को 0.799 अंक की बढ़त दिला दी। बैलेंस बीम में चीन की बढ़त और मजबूत हुई। झांग छिंगयिंग ने 15.066 अंक की शानदार प्रस्तुति देकर टीम की बढ़त तीन अंकों से अधिक कर दी। फ्लोर एक्सरसाइज में चीन ने दबाव के बीच बढ़त कायम रखी और स्वर्ण पक्का किया। जापान की अनुभवी सुगिहारा ने 13.966 अंक की बेहतरीन प्रस्तुति दी, लेकिन तब तक चीन की बढ़त निर्णायक हो चुकी थी। दू सियू ने मुकाबले के बाद कहा कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और टीम के कुल स्कोर में योगदान देने की कोशिश की। वहीं छ्यू छियुआन ने टीम की एकजुटता को सफलता का अहम आधार बताया। उन्होंने कहा कि गलतियों के समय टीम की सदस्य एक-दूसरे का सहारा बनती रहीं और टीम भावना इस समूह की सबसे मूल्यवान ताकत रही।

मुरादाबाद के देव और यथार्थ सूद राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता के लिए चयनित

मुरादाबाद। मुरादाबाद मॉडर्न पब्लिक स्कूल के दो होनहार खिलाड़ियों, देव और यथार्थ सूद ने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर उत्तर प्रदेश की आर्म रेसलिंग टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। दोनों खिलाड़ी आगामी 48वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता - 2026 में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2 से 5 अक्टूबर 2026 तक शेर-ए-कश्मीर इनडोर स्टेडियम, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी देव जूनियर बालक वर्ग (अंडर 50 किलो भार वर्ग, राइट हैंड) हैं। यथार्थ सूद जूनियर बालक वर्ग (अंडर 80 किलो भार वर्ग, राइट हैंड) विगत वर्ष भी जीता था पदकरू यह दोनों खिलाड़ी लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इन्होंने पिछले वर्ष भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे और मॉडर्न पब्लिक स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन किया था। इस बार भी उनसे इसी तरह के उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद है। यह गौरवशाली टीम स्कूल के कुशल खेल प्रशिक्षक शाहवेज़ अली के नेतृत्व में इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए रवाना होगी। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चुनौती पेश करने के लिए दोनों खिलाड़ी 30 सितंबर 2026 को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस शानदार उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन में हर्ष का माहौल है। विद्यालय के प्रशासक सऊद आलम, प्रधानाचार्य मोहम्मद अहसन और कॉर्डिनेटर सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से चयनित खिलाड़ियों और उनके कोच को बधाई दी।

एशियाई खेल : सतनाम- सलमान ने रोइंग में जीता कांस्य, बलराज पंवार पदक से चूके

आइची-नगोया (जापान)। भारतीय रोइंग जोड़ी सतनाम सिंह और सलमान खान ने एशियाई खेल 2026 में पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत की पदक संख्या में इजाफा किया। वहीं, पुरुष सिंगल स्कल्स में बलराज पंवार पदक जीतने से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। सतनाम और सलमान ने गुरुवार को फाइनल में 6 मिनट 13.25 सेकंड का समय निकाला। वे स्वर्ण पदक जीतने वाली चीन की यी शुदी और नी यिदे की जोड़ी से 3.48 सेकंड पीछे रहे। उज्बेकिस्तान के मेखरोजबेक मामातकुलोव और पावेल सोरिन ने रजत पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने रेस के शुरुआती चरण में शानदार प्रदर्शन किया। सतनाम और सलमान 500 मीटर, 1000 मीटर और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर बने रहे। एक समय वे चीनी जोड़ी से केवल आधा सेकंड पीछे थे, लेकिन आखिरी चरण में उनकी रफ्तार थोड़ी कम हुई और उन्हें कांस्य से संतोष करना पड़ा। पुरुष सिंगल स्कल्स के फाइनल में बलराज पंवार भी पदक की दौड़ में बने हुए थे। वह 500 मीटर, 1000 मीटर और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन अंतिम 500 मीटर में उज्बेकिस्तान के शखबोज खोल्मुर्जाएव और जापान के तात्सुया सकुरामा ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। बलराज चौथे स्थान पर रहे।

मजबूत टेस्ट टीम ही मजबूत क्रिकेट टीम, रेड-बॉल क्रिकेट हमारी प्राथमिकता: गौतम गंभीर

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि देश में मजबूत टेस्ट क्रिकेट होना पूरे क्रिकेट ढांचे के लिए बेहद जरूरी है और रेड-बॉल क्रिकेट टीम की प्राथमिकता बना रहेगा। गंभीर ने भारत के नए घरेलू सत्र से पहले जियोस्टार से बातचीत में टीम के साथ अपने अब तक के कार्यकाल, टेस्ट क्रिकेट से मिली सीख और अलग-अलग कप्तानों के साथ काम करने के अनुभव पर बात की। गंभीर ने अपने कार्यकाल के बारे में कहा कि पिछले दो साल उतार-चढ़ाव से भरे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'दो साल पलक झपकते नहीं गुजर गए। मेरे हिस्से में भी उतार-चढ़ाव रहे हैं। मेरी अपनी असफलताएं और सफलताएं रही हैं। लेकिन मेरा हमेशा मानना रहा है कि जब आप इस तरह की जिम्मेदारी लेते हैं तो उतार-चढ़ाव आते ही हैं। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, एकदिवसीय क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट, मुझे सफलता मिली है, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा, लेकिन असफलताएं भी मिली हैं और मैं उन्हें भी पूरी तरह स्वीकार करता हूं।

टेस्ट क्रिकेट में बदलाव और हालिया परिणामों पर गंभीर ने कहा कि इंग्लैंड दौरे के बाद टीम ने अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेला है, लेकिन टीम अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के जाने के बाद उनकी जगह भरना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमने इंग्लैंड के बाद से काफी अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेला है। मैं यह नहीं कह रहा कि हम अभी पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में काफी बदलाव हुआ है। खासकर रोहित, विराट और अश्विन के जाने के बाद ऐसे खिलाड़ियों को बदलना बेहद मुश्किल है। इन खिलाड़ियों के पास जितनी प्रतिभा और अनुभव था और उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए रेड-बॉल क्रिकेट में जो किया है, उनकी जगह लेना किसी के लिए आसान नहीं होगा। इसमें समय लगेगा। गंभीर ने कहा कि अगर सही खिलाड़ियों को लगातार समर्थन दिया जाता रहा तो भारतीय क्रिकेट लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में दबदबा बना सकता है। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सही खिलाड़ियों का समर्थन करते रहे तो भारतीय क्रिकेट लंबे समय तक रेड-बॉल क्रिकेट में दबदबा बना सकता है। जब आप नए खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट में लाते हैं तो उनकी उम्र और उनके मैचों की संख्या देखते हैं और उन्हें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कितना महत्वपूर्ण है। मैं इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि एक मजबूत टेस्ट क्रिकेट वाला देश ही एक मजबूत क्रिकेट देश होता है। इसलिए रेड-बॉल क्रिकेट अभी भी हमारी प्राथमिकता है। गंभीर ने रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के साथ अलग-अलग प्रारूपों में काम करने के अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि सभी कप्तानों ने हमेशा टीम को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा। उन्होंने कहा, 'मैंने चार कप्तानों के साथ काम किया है- रोहित, सूर्य, अब शुभमन और श्रेयस। जिन भी कप्तानों के साथ मैंने काम किया, उनकी पहली सोच हमेशा टीम रही। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे चार लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने हमेशा खुद से पहले टीम को रखा। उन्होंने कहा कि कप्तान की सोच और खेल को देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन अगर उसकी नीयत सही है तो सहयोगी स्टाफ के लिए काम आसान हो जाता है।

एशियाई खेल क्रिकेटः अफगानिस्तान ने जापान को 48 रन से हराकर जीत से खोला खाता

निसिन। अफगानिस्तान ने गुरुवार को एशियाई खेल 2026 में पुरुष क्रिकेट के अपने पहले मुकाबले में मेजबान जापान को 48 रन से हराकर शानदार शुरुआत की। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए ग्रुप-ए के मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 129/6 रन बनाए, जिसके जवाब में जापान की टीम 19.3 ओवर में 81 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की जीत में पदार्पण कर रहे लेग स्पिनर अरब गुल मोमंद ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 8 रन देकर चार विकेट झटके। उनके अलावा बाएं हाथ के स्पिनर नांगेयालिया खारोटी ने तीन विकेट लिए, जबकि अब्दुल्ला अहमदजई और नजीबुल्लाह जादरान ने भी विकेट हासिल किए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। हसन ईसाखिल 10 गेंदों में तीन रन बनाकर आउट हुए।

पदार्पण कर रहे सलामी बल्लेबाज मोहम्मद अकरम ने 29 गेंदों में 34 रन बनाकर पारी को संभाला। एक समय अफगानिस्तान का स्कोर 15.1 ओवर में 79/4 था। इसके बाद कप्तान दरवेश रसूली और विकेटकीपर मोहम्मद इशाक ने तेजी से रन जुटाए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 25 गेंदों में 44 रन की साझेदारी की। रसूली ने 27 गेंदों में 29 और इशाक ने 17 गेंदों में 25 रन बनाए, जिससे अफगानिस्तान 20 ओवर में 129/6 तक पहुंच गया। जापान के लिए इब्राहिम ताकाहाशी और शोमा सुगाया-स्लेटर ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे जापान को शुरुआती झटका पहले ही ओवर में लगा, जब अब्दुल्ला अहमदजई ने लाचलान यामामोटो-लेक को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया। हालांकि रियो सकुरानो-थॉमस ने 23, केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग ने 14 और बेंजामिन इटो-डेविस ने 17 रन बनाकर जापान को मुकाबले में बनाए रखा। जापान का स्कोर एक समय 7.3 ओवर में 53/1 था और उसे 75 गेंदों में 77 रन की जरूरत थी। इसके बाद अफगानिस्तानी स्पिनरों ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। नांगेयालिया खारोटी और नजीबुल्लाह जादरान ने विकेट निकाले, जबकि अरब गुल मोमंद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटक लिए। 60/3 के स्कोर के बाद जापान ने बिना कोई रन जोड़े तीन विकेट गंवा दिए और देखते ही देखते उसका स्कोर 63/8 हो गया। अरब गुल ने दो मेडन ओवरों में दो-दो विकेट लेकर जापान की पारी की कमर तोड़ दी।

एशियाई खेल : मानुष शाह ने जीत के साथ शुरू किया एकल अभियान

आइची-नगोया (जापान)। एशियाई खेल 2026 में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन जारी है। मानुष शाह ने पुरुष एकल स्पर्धा में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि श्रीजा अकुला-सिंड्रेला दास और दीया चितले-यशस्विनी घोरपड़े की जोड़ियों ने महिला युगल में अपने-अपने मुकाबले जीते।

मानुष शाह ने पुरुष एकल के शुरुआती मुकाबले में मलेशिया के वोंग क्यू शेन को सीधे चार गेम में 4-0 से हराया। मानुष ने मुकाबला 11-9, 14-12, 11-7, 11-4 से अपने नाम किया। महिला युगल में स्त्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास की जोड़ी ने मंगोलिया की बोलोर-एरदेने बातमुंख और बुरेनजार्गल सांजा को 3-0 से हराकर विजयी शुरुआत की। भारतीय जोड़ी ने 11-5, 11-4, 12-10 से मुकाबला जीता। इससे पहले दीया चितले और यशस्विनी घोरपड़े ने महिला युगल के दूसरे दौर में ईरान की सेटायश इलूखानी और मशिद अश्तारी को 3-0 से हराया था। भारतीय जोड़ी ने 11-2, 11-2, 11-4 से एकतरफा जीत दर्ज की। एथलेटिक्स में जय कुमार, किरण पहल, मनु टीएस और पूवम्मा एमआर की भारतीय चौकड़ी ने

मिश्रित 4म400 मीटर रिले के फाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम अपनी हीट में 3 मिनट 16.23 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही। चीन 3:15.97 के समय के साथ पहले और संयुक्त अरब अमीरात 3:17.00 के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तैराकी में आर्यन नेहरा पुरुष 800 मीटर फ्रीस्टाइल के फाइनल बी में 8 मिनट 2.52 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यह पदक स्पर्धा का फाइनल नहीं था और इसमें मुख्य फाइनल से बाहर रहने वाले तैराकों ने हिस्सा लिया। पुरुष 4म100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में बेनेडिक्शन बेनिस्टन, अनीश सुनील, आकाश मणि और गितेश शाह की भारतीय टीम 3 मिनट 23.51 सेकंड के समय के साथ 13 टीमों में 12वें स्थान पर रही। अपनी हीट में भारतीय टीम छठे स्थान पर रही।

एशियन गेम्स में मप्र के जय मीना ने रचा इतिहास, सॉफ्ट टेनिस में भारत को दिलाया कांस्य पदक

भोपाल,एजेंसी। मध्य प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी जय मीना ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया है। जापान के आइची-नागोया में जारी 20वें एशियन गेम्स में उन्होंने बुधवार को सॉफ्ट टेनिस के पुरुष एकल वर्ग में भारत के लिए ऐतिहासिक कांस्य पदक सुनिश्चित किया। इसके साथ ही वह एशियन गेम्स के इतिहास में सॉफ्ट टेनिस में भारत को पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

इससे पहले पुरुष एकल के सेमीफाइनल में जय मीना का सामना जापान के ताकुया कुरोसाका से हुआ। जय ने मुकाबले में शानदार जुझारूपन दिखाते हुए कड़ी चुनौती पेश की। हालांकि, सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही जय ने भारत के लिए कांस्य पदक पक्का कर इतिहास रच दिया। जय मीना ने क्वार्टरफाइनल मुकाबले में फिलीपींस के खिलाड़ी के खिलाफ बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। निर्णायक चरण तक पहुंचे इस मुकाबले में जय के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें अंतिम चार में स्थान दिलाया और भारत का पदक सुनिश्चित हुआ। मप्र के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जय मीना को ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जय मीना की उपलब्धि मध्य प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। सॉफ्ट टेनिस में भारत को एशियन गेम्स का पहला पदक दिलाकर जय ने भारतीय खेल इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। उनकी यह सफलता प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है। जय मीना

ने वर्ष 2022 में गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने पुरुष टीम और युगल स्पर्धाओं में भी मध्य प्रदेश के पदक अभियान में योगदान दिया। वर्ष 2025 में वे पुरुष एकल के नेशनल चैंपियन बने। लगातार राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने एशियन गेम्स में ऐतिहासिक पदक जीतकर अपनी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है।

जय मीना ने वर्ष 2024 में वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में अंडर-21 मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीतकर भी भारतीय सॉफ्ट टेनिस में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की थी। उन्होंने आध्या तिवारी के साथ मिलकर यह पदक हासिल किया था और यह विश्व चैंपियनशिप में भारत की पहली पदक विजेता जोड़ी बनी थी। जय मीना का सफर भी बेहद दिलचस्प रहा है। देवास के पायोनियर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने पहली बार सॉफ्ट टेनिस कोर्ट देखा। शुरुआत में वे केवल खिलाड़ियों को देखने और बॉल बॉय के तौर पर मदद करने जाते थे। धीरे-धीरे इस खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने स्वयं खेलना शुरू किया। स्कूल और जिला प्रतियोगिताओं से आगे बढ़ते हुए उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई तथा महज 14 वर्ष की उम्र में जापान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया था। जय मीना का कांस्य पदक भारतीय सॉफ्ट टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एशियन गेम्स के मंच पर भारत के लिए इस खेल का पहला पदक जीतकर जय ने न केवल देश का गौरव बढ़ाया, बल्कि मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभा को भी अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है।

एशियाई खेलः भारतीय टेबल टेनिस जोड़ी दीया-यशस्विनी ने महिला युगल के दूसरे दौर में दर्ज की जीत

आइची-नगोया (जापान),एजेंसी। एशियाई खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। टेबल टेनिस में दीया चितले और यशस्विनी घोरपड़े की जोड़ी ने गुरुवार को महिला युगल के दूसरे दौर में ईरान को 3-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं, वुशु में रोशिबिना देवी ने रजत और रोइंग में सतनाम सिंह-सलमान खान की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। टेबल टेनिस में दीया और यशस्विनी ने ईरान की सेटायश इलूखानी और मशिद अश्तारी की जोड़ी को एकतरफा मुकाबले में 11-2, 11-2, 11-4 से हराया।

वुशु की महिलाओं की 60 किग्रा सांडा स्पर्धा में रोशिबिना देवी को फाइनल में चीन की झांग शियाओयू के खिलाफ 0-2 से हार मिली। झांग ने दोनों राउंड 5-0 से अपने नाम किए। इसके बावजूद रोशिबिना ने लगातार दूसरे एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। 2018 में कांस्य और 2022 तथा 2026 में रजत जीतकर वह एशियाई खेलों में वुशु में लगातार तीन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रोइंग के पुरुष डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान ने 6 मिनट 13.25 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी 500, 1000 और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम चरण में चीन की जोड़ी से पीछे रह गई। चीन के यी शुदी और नी यिदे ने स्वर्ण, जबकि मेखरोजबेक मामातकुलोव और पावेल सोरिन ने रजत पदक जीता। पुरुष सिंगल स्कल्स में बलराज

पंवार पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। वह 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अंतिम 500 मीटर में उज्बेकिस्तान के शखबोज खोल्मुर्जाएव और जापान के तात्सुया सकुरामा से पीछे हो गए। बलराज ने 6 मिनट 54.80 सेकंड का समय निकाला। तैराकी में भारत के बेनेडिक्शन बेनिस्टन पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई की हीट में 23.87 सेकंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहे। सभी हीट के बाद वह 12वें स्थान पर हैं और शीर्ष 10 खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंचते हैं। वह फाइनल के लिए रिजर्व में हैं। कैनो स्प्रिंट में मेघा प्रदीप महिलाओं की एकल 200 मीटर सेमीफाइनल में 51.093 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं। शीर्ष तीन खिलाड़ी फाइनल में पहुंचने के कारण मेघा का अभियान यहीं समाप्त हो गया। एथलेटिक्स में हेप्टाथलॉन की 100 मीटर बाधा दौड़ में अनामिका अनीश कोझिंजापरम्बिल 14.80 सेकंड के समय के साथ अपनी हीट में पांचवें और अंतिम स्थान पर रहीं। उन्होंने 868 अंक हासिल किए। दूसरी हीट में पूजा 14.61 सेकंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहीं और उन्हें 894 अंक मिले। इन परिणामों के साथ भारत के एशियाई खेलों में पदकों की संख्या 14 हो गई है। भारत ने अब तक एक स्वर्ण, छह रजत और सात कांस्य पदक जीते हैं।

एशियाई खेलः जोशना- वेलावन की जोड़ी स्क्वैश मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में

आइची-नगोया। एशियाई खेल 2026 में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। स्क्वैश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार की जोड़ी ने मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं, वुशु में रोशिबिना देवी ने रजत और रोइंग में सतनाम सिंह-सलमान खान ने कांस्य पदक जीता। मिश्रित युगल के मुकाबले में जोशना और वेलावन ने अपने ही देश के सूरज चंद और शमीना रियाज को 2-0 (11-7, 11-10) से हराया। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 11-7 से जीता, जबकि दूसरा गेम 11-10 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में सूरज और शमीना ने 7-9 से पिछड़ने के बाद स्कोर 9-9 से बराबर किया, लेकिन जोशना और वेलावन ने अनुभव का फायदा उठाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।

वुशु की महिलाओं की 60 किग्रा सांडा स्पर्धा में रोशिबिना देवी ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें चीन की झांग शियाओयू के खिलाफ 0-2 से हार मिली। झांग ने दोनों राउंड 5-0 से जीते। रोशिबिना ने 2018 में कांस्य और 2022 में रजत पदक जीता था। 2026 में रजत के साथ वह एशियाई खेलों में वुशु में लगातार तीन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रोइंग के पुरुष डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान ने 6 मिनट 13.25 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी 500, 1000 और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर रही, लेकिन अंतिम चरण में पीछे हो गई। चीन की यी शुदी और नी यिदे की जोड़ी ने स्वर्ण, जबकि मेखरोजबेक मामातकुलोव और पावेल सोरिन ने रजत जीता। पुरुष सिंगल स्कल्स में बलराज पंवार पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। वह 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अंतिम 500 मीटर में उज्बेकिस्तान के शखबोज खोल्मुर्जाएव और जापान के तात्सुया सकुरामा से पीछे हो गए। बलराज ने 6 मिनट 54.80 सेकंड का समय निकाला। इन पदकों के साथ एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या 14 हो गई है। भारत ने अब तक एक स्वर्ण, छह रजत और सात कांस्य पदक जीते हैं।

जलवायु आपदा से उबरने के लिए नेपाल को दीर्घकालीन अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी: विदेशमंत्री शिशिर खनाल

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल ने जलवायुजनित आपदाओं से प्रभावित नेपाल में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालीन अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर आयोजित जी-7 विकास मंत्रीस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए खनाल ने नेपाल में हाल की जलवायुजनित आपदा की स्थिति का उल्लेख किया और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पीड़ितों के पुनर्वास, जलवायु वित्त, आपदा पूर्व तैयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग और हिमालयी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर जी-7 के सहयोग और साझेदारी का आह्वान किया।

नेपाल का प्रतिनिधितत्व करते हुए खनाल ने जलवायु आपदा की कठिन परिस्थितियों में नेपाल के प्रति एकजुटता और सहयोग के लिए जी-7 सदस्य देशों तथा अन्य मित्र राष्ट्रों के प्रति नेपाल सरकार और नेपाली जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'नेपाल जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, लचीलापन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में जी-7 के नेतृत्व की उच्च सराहना करता है।' उन्होंने बैठक के आयोजन के लिए जी-7 की अध्यक्षता कर रहे फ्रांस को भी धन्यवाद दिया। मंत्री खनाल ने कहा कि हाल की जलवायुजनित आपदा से नेपाल में मानवीय और भौतिक क्षति बेहद व्यापक हुई है। बाढ़ से घरों, सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों और जलविद्युत बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इससे जनजीवन के साथ-साथ आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की

आवश्यकता होगी। आपदा के वैज्ञानिक अध्ययन का काम जारी होने की जानकारी देते हुए खनाल ने कहा कि शुरुआती विवरणों के अनुसार तेजी से गर्म हो रहे हिमालयी वातावरण में बर्फ, चट्टान, पानी और अस्थिर भू-आकृतियों के बीच जटिल अंत:क्रिया के कारण यह आपदा उत्पन्न हुई हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसका विस्तृत अध्ययन अभी जारी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ भूगर्भीय, हिमनदीय और जलविज्ञान संबंधी कारणों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

खनाल ने कहा, 'जलवायु परिवर्तन नेपाल के लिए अब दूर का खतरा नहीं है। यह हमारी वर्तमान वास्तविकता है और इसके प्रभाव की तीव्रता तथा आवृत्ति दोनों बढ़ रही हैं।' उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जनधन और आजीविका को नुकसान पहुंचने के साथ लंबे प्रयासों से हासिल विकास की उपलब्धियां भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय, नदियां, समुदाय और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे बाढ़, भूस्खलन, हिमनदीय जोखिम तथा अन्य जलवायुजनित आपदाओं के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं। खनाल ने कहा कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नेपाल का योगदान बेहद कम है, लेकिन इसके बावजूद देश को जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नेपाल को और अधिक सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा, 'नेपाल का वैश्विक उत्सर्जन में योगदान बेहद कम है। लेकिन विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से लेकर हिमनदों के पिघलने तक के जलवायुजनित प्रभावों को हम असमान रूप से झेल रहे हैं। पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल की पांच प्रमुख अपेक्षाएं सामने रखते हुए खनाल ने सबसे पहले पुनर्वास के लिए साझेदारी की आवश्यकता बताई। मानवीय सहायता के लिए मित्र देशों से मिले सहयोग और सद्भावना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अनुदान तथा रियायती वित्तीय संसाधनों सहित समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयास जरूरी हैं। दूसरी प्राथमिकता के रूप में उन्होंने जलवायु वित्त तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाली हानि और क्षति (स्रुह्यह्य ड्डठ्ठस्र ष्ठड्डद्वड्डद्दद्ग) के लिए वित्तीय सहायता विकासशील और जलवायु जोखिम वाले देशों को तेज, सरल और सहज तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नेपाल ने हानि और क्षति कोष से संबंधित वित्तीय व्यवस्था के लिए अनुरोध किया है और अब सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। खनाल ने आपदा रोकथाम और पूर्व तैयारी में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने पूर्व चेतावनी प्रणाली, जलवायु संबंधी जानकारी, जल एवं मौसम सेवाओं, जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे तथा समुदाय आधारित आपदा पूर्व तैयारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने जी-7 और अन्य साझेदार देशों से जलवायुजनित आपदाओं की बढ़ती गंभीरता से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की अपील की। उन्होंने बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से तेजी से, कम लागत पर और आसानी से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। खनाल ने कहा, 'समय पर उपलब्ध वित्तीय संसाधन केवल एक वित्तीय साधन नहीं, बल्कि जलवायुजनित झटकों से बार-बार प्रभावित होने वाले जोखिमग्रस्त देशों के लिए जीवनरेखा हैं।

एक नजर

ईयू ने फ्रांस से निष्कासित रूसी टिप्पणीकार फेडोरोवा पर लगाया प्रतिबंध

ब्रसेल्स,एजेंसी। यूरोपीय संघ ने रूस की मीडिया हस्ती और आरटी फ्रांस की पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जेनिया फेडोरोवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेडोरोवा को पिछले महीने फ्रांस से निष्कासित किया गया था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन पर क्रेमलिन समर्थक प्रचार और रूस की गतिविधियों के पक्ष में कथित तौर पर काम करने के आरोप लगाए थे। 27 देशों के यूरोपीय संघ ने अपने प्रतिबंध संबंधी फैसले में कहा कि 45 वर्षीय फेडोरोवा फ्रांस और यूरोपीय संघ में रूस समर्थक विचारों के प्रसार में सक्रिय रही हैं। यह गतिविधियां यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के संदर्भ में की गईं। फेडोरोवा को अगस्त में फ्रांस से औपचारिक रूप से निष्कासित किया गया था। इससे पहले उन्होंने उस न्यायिक फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। अपील खारिज होने के बाद निष्कासन का रास्ता साफ हुआ। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो ने कहा कि फ्रांस और यूरोपीय संघ अपने क्षेत्र में रूस की अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को बिना परिणाम के जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फेडोरोवा फ्रांस में रूस टुडे (आरटी) के फ्रांसीसी चैनल की प्रमुख रह चुकी हैं। रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद फ्रांस में आरटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फेडोरोवा ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें 'सेंसरशिप' बताया है। उनका कहना है कि जब निष्कासन आदेश लागू हुआ, उस समय वह छुट्टी मनाने के लिए फ्रांस से बाहर थीं।

लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान की बहनों उजमा और नोरीन की हिरासत रोकने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार

इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों उजमा खान और नोरीन नियाजी को हिरासत में रखने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर कहा है कि जवाब मिलने के बाद हिरासत आदेशों पर रोक की मांग पर फैसला किया जाएगा। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (एमपीओ) अध्यादेश की धारा 3 के तहत 30 दिन की हिरासत के आदेश जारी किए थे।सुनवाई के दौरान दोनों महिलाओं के वकीलों ने दलील दी कि उजमा और नोरीन राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हैं और उनकी हिरासत का कोई उचित आधार नहीं है। वकीलों ने यह भी कहा कि उजमा खान को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में पहले ही बरी किया जा चुका है। उन्होंने दोनों के हिरासत आदेश तत्काल निलंबित करने की मांग की। यह याचिका इमरान खान की तीन बहनों अलीमा खान, नोरीन नियाजी और उजमा खान को पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद दायर की गई है। इस मामले में लाहौर के डिप्टी कमिश्नर, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, गृह विभाग के सचिव और कोट लखपत जेल के अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया है।

ईरान की पड़ोसी देशों को चेतावनी, अमेरिकी प्रतिबंधों में सहयोग पर मार्ग प्रभावित करने की धमकी

तेहरान। अमेरिका की ओर से ईरानी एयरलाइंस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा के बीच ईरान ने पड़ोसी देशों को इन पाबंदियों को लागू करने में सहयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों में सहयोग करने वाले देशों को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के अर्ध-सरकारी स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क (एसएनएन) को बुधवार को दिए एक साक्षात्कार में रेजाई ने पड़ोसी देशों से अमेरिकी कदमों में शामिल होने से बचने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से ईरानी वाणिज्यिक उड़ानों, यात्री सेवाओं और माल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने में सहयोग न करने को कहा। रेजाई के मुताबिक, यदि क्षेत्र के देश ईरान के हवाई परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने में सहयोग करते हैं, तो जवाब में उन देशों के हवाई अड्डों और विमानन मार्गों को भी बंद करने या बाधित करने की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने अमेरिका के साथ भविष्य में संभावित बातचीत को लेकर भी सख्त रुख का संकेत दिया। रेजाई ने कहा कि वाशिंगटन के साथ आगे की वार्ता और होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने जैसे मुद्दे ईरान की शर्तों पर निर्भर होंगे।

यूक्रेन में रूसी हमलों में सात लोगों की मौत, कीव में ड्रोन हमलों से मचा हड़कंप

कीव। यूक्रेन में बुधवार को रूसी हमलों की एक नई लहर में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। हमलों में राजधानी कीव समेत देश के कई हिस्सों में लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। कीव में दो लोगों की मौत हुई, जबकि स्थानीय अधिकारियों के अनुसार 41 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने राजधानी पर बड़ी संख्या में ड्रोन दागे। यह हमला ऐसे समय हुआ जब जेलेंस्की न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले थे। उनके भाषण में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए बेहतर वायु रक्षा व्यवस्था की मांग किए जाने की उम्मीद थी। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, रूसी ड्रोन ने पेट्रोल पंपों, कार्यालयों, कारोबारी प्रतिष्ठानों और रेलवे से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। यूक्रेन रेलवे के प्रमुख ओलेक्सांद्र पर्त्सोव्स्की ने कहा कि कीव का रेल नेटवर्क भी हमले की चपेट में आया है। उन्होंने यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। पूर्वी डोनबास क्षेत्र में क्रामातोर्स्क के पश्चिम स्थित ओलेक्सांद्रिव्का में एक आवासीय इमारत पर हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हुई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के मानवाधिकार आयुक्त दिमित्रो लुबिनेत्स ने कहा कि चार अन्य लोग घायल हुए हैं और मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है।

व्हाइट हाउस में शी जिनपिंग का संदेश, चीन-अमेरिका संबंधों को स्थिर दिशा में आगे बढ़ाने पर जोर

वाशिंगटन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दशक से अधिक समय बाद अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान चीन-अमेरिका संबंधों में दोस्ती और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर व्हाइट हाउस पहुंचे शी ने कहा कि उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों के हित में काम करने के उद्देश्य से है।

व्हाइट हाउस के ग्रैंड फोयर में तैयार बयान में शी ने कहा कि चीन और अमेरिका दुनिया में बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देशों पर मानव विकास तथा प्रगति को आगे बढ़ाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप के साथ मिलकर चीन-अमेरिका संबंधों को भविष्य की ओर स्थिर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम करने को तैयार हैं। शी ने कहा कि दोनों देशों के हित एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और साथ मिलकर काम करने की काफी गुंजाइश है। उनके मुताबिक, चीन-अमेरिका सहयोग दुनिया की हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन इसके बिना कई वैश्विक समस्याओं का समाधान मुश्किल होगा। शी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को भी दोनों देशों के बीच सहयोग का अहम क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका एआई के क्षेत्र में अग्रणी देश हैं और दोनों के पास इस तकनीक को मानव हित में विकसित और प्रबंधित करने की क्षमता तथा जिम्मेदारी है। शी ने कहा कि एआई का विकास हमेशा मानव नियंत्रण में रहना चाहिए और इसका इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए।

ट्रंप और शी की बातचीत में एआई के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। शी ने अमेरिका और चीन के बीच पांडा को लंबे समय से चले आ रहे 'मैत्री दूत' के रूप में भी याद किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में चीन के दो विशाल पांडा अटलांटा के एक चिड़ियाघर पहुंचेंगे। अटलांटा चिड़ियाघर ने बताया है कि दोनों पांडा के नाम पिंग पिंग और फू शुआंग है। बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच पांडा कूटनीति की शुरुआत 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा के बाद हुई थी।

यूएन महासभा में अब्बास का अमेरिकी प्रशासन पर निशाना, कहा- फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को रोका जाना गलत

न्यूयॉर्क,एजेंसी। फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को वर्चुअली माध्यम से संबोधित करते हुए अमेरिकी प्रशासन द्वारा उन्हें लगातार दूसरे वर्ष व्यक्तिगत रूप से यूएन में आने से रोकने पर आपत्ति जताई। उन्होंने अमेरिका से फिलिस्तीनी प्राधिकरण पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और रामल्ला के साथ बातचीत फिर शुरू करने की अपील की।

अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनी नेतृत्व अमेरिकी प्रतिबंधों और उन्हें लागू करने के लिए दिए गए आधारों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने व्यापक राष्ट्रीय सुधार कार्यक्रम लागू किया है और अंतरराष्ट्रीय कानून तथा हिंसा एवं आतंकवाद से दूरी बनाए रखने की प्रतिबद्धता निभाई है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रुख करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अब्बास ने अमेरिकी कदम को मेजबान देश के रूप में अमेरिका के दायित्वों के विपरीत बताया और वाशिंगटन से फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ संवाद बहाल करने का आग्रह किया। दरअसल, अमेरिका ने पिछले सप्ताह फिलिस्तीनी अधिकारियों पर पिछले वर्ष लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ाने की घोषणा की थी। अमेरिकी पक्ष ने इसके लिए ऐसे कदमों का हवाला दिया था, जिनमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई, एकतरफा फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को आगे बढ़ाना

तथा आतंकवाद या हिंसा से जुड़े आरोप शामिल हैं।

इजराइल पर गंभीर आरोप

अब्बास ने अपने संबोधन में इजराइल पर गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ 'नरसंहार की जंग' चलाने और वेस्ट बैंक में बस्तियों तथा बसने वालों की हिंसा को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार तेज हो रहा है और क्षेत्र को अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा रहा है। अब्बास ने भूमि कब्जाने, घरों को गिराने, चौकियों और छापेमारी जैसी कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया और इन्हें भेदभाव तथा विस्थापन से जुड़ी नीतियों का हिस्सा बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इजरायल फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन बाहर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यरुशलम को अलग-थलग करने और उसके स्वरूप को बदलने का भी आरोप लगाया। अब्बास के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियां केवल दो-राष्ट्र समाधान और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए ही नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी लोगों के अपने क्षेत्र में भविष्य के लिए भी खतरा पैदा कर रही हैं। अब्बास ने यूएन सदस्य देशों से अपील की कि वे 1948 जैसी किसी और 'नकबा' और बड़े पैमाने पर विस्थापन या हत्याओं को दोहराने की अनुमति न दें।

राष्ट्रपति ट्रंप की एक ही शर्त, ईरान को शांति समझौता चाहिए तो पहले परमाणु कार्यक्रम छोड़ेः रुबियो

न्यूयॉर्क,एजेंसी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (विदेशमंत्री) मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान से अगर समझौता होता है तो उसे हर हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौता करने के लिए तैयार हैं। मगर एक शर्त के साथ। वह शर्त है ईरान को परमाणु हथियारों का मोह त्यागना होगा। तब समझौता होगा और ईरान फिर महान देश बन सकेगा। उन्होंने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क के आलीशान पैलेस होटल में खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के ईरान मुद्दे के अलावा अन्य सवालों के सौहार्दपूर्ण माहौल में जवाब दिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (विदेश मंत्रालय) की वेबसाइट ने सवाल-जवाब के अलावा संवाददाता सम्मेलन का वीडियो साझा किया है।

संवाददाता सम्मेलन में पहुंचते ही रुबियो ने कहा कि ठीक है, आगे बढ़िए। उनसे पहला सवाल ईरान पर पूछा गया- कल ईरानियों के साथ अमेरिका की क्या मांगें थीं और क्या समझौता (एमओयू)में लौटने पर कोई चर्चा हुई या अमेरिका के लिए शर्तें बदल गई हैं? विदेशमंत्री रुबियो ने कहा, ''देखिए, कल की बातचीत उस प्रक्रिया में शामिल कुछ मध्यस्थों के साथ हुई। मैं इसे किसी एक दिशा में नहीं बताना चाहता। मुझे लगता है कि इसकी समझ बिल्कुल साफ है। याद रखिए, यहां सबसे मुख्य मुद्दा - जिसे राष्ट्रपति ने कल दुनिया के सामने अपने भाषण में जोर देकर कहा - वह यह है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। सब कुछ इसी बात से जुड़ा है। उन्होंने कहा, '' हम समझते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक मुद्दा है। जलडमरूमध्य का दक्षिणी रास्ता खुला है। हर दिन वहां से ज्यादा से ज्यादा तेल के बैरल गुजर रहे हैं। यह रास्ता अमेरिकी सेना की कोशिश की वजह से खुला है। अमेरिकी सेना जहाजों की सुरक्षा भी कर रही है और उसने बारूदी सुरंगें (माइंस) भी हटाई हैं। और यह सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच, होर्मुज जलडमरूमध्य में एकमात्र नाकाबंदी वह है जो हमने ईरान पर लगाई है, क्योंकि तेहरान जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है।आज सुबह भी उसने ऐसा ही किया। अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी मुद्दा है। रुबियो ने कहा, ''लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। हम हर बातचीत में यह बात रखते हैं। मैं इन बैठकों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर ईरान के साथ कोई समझौता होता है तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा। इसमें लंबा समय लगेगा। इस प्रक्रिया में मध्यस्थ भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने कहा है कि वे समझौते के लिए तैयार हैं, जिससे ईरान महान और समृद्ध देश बन सके। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार पाने की अपनी इच्छा पर अड़ा रहता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला देश है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास कई विकल्प हैं।

तारिक रहमान ने बांग्लादेश के रोहिंग्या मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचा

न्यूयॉर्क,एजेंसी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपने देश के रोहिंग्या मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर 'रोहिंग्या संकट: लंबे समय तक विस्थापन से न्याय और जवाबदेही के साथ टिकाऊ समाधान के लिए एक नई अपील' विषयक सम्मेलन में विचार रखे। उन्होंने पांच सूत्रीय प्रस्ताव रखते हुए रोहिंग्याओं को म्यांमार भेजने का भरोसेमंद रोडमैप बनाने की अपील की। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, तारिक रहमान ने कहा कि अब विस्थापन को खत्म करने की ओर बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, 'अब समय आ गया है कि सहानुभूति से असली कारणों और उनके समाधानों की तलाश की जाए। भरोसेमंद कार्रवाई की जाए।' प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव बांग्लादेश में शरण लिए हुए 1.2 मिलियन से ज्यादा रोहिंग्याओं की बुरी हालत पर रोशनी डालते हुए दिया। तारिक विश्व समुदाय से उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए हालात बनाने के लिए पक्के इरादे के साथ अपनी जिम्मेदारी उठाने की अपील की।

उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश नहीं चाहता कि रोहिंग्या हमेशा के लिए बेघर रहें। हम चाहते हैं कि वे म्यांमार में अपने घरों में सुरक्षित, अपनी मर्जी से, सम्मान के साथ और अपने अधिकारों की रक्षा के साथ लौटें।' तारिक ने आगे कहा, 'बांग्लादेश ने इंसानियत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर जरूरी

हालात बनते हैं तो बांग्लादेश उनकी वापसी में मदद करने के लिए तैयार रहेगा।' इस सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश और गाम्बिया ने संयुक्त रूप से किया। इसमें अलग-अलग देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने म्यांमार में रोहिंग्याओं समेत आम लोगों के खिलाफ हिंसा खत्म करने की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि वापसी के लिए भरोसा वापस पाने के लिए उनके अपने देश में उनके बुनियादी अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। रोहिंग्याओं की लगातार वापसी पक्का करने के लिए न्याय और जवाबदेही जरूरी है, साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जवाबदेही तय करने में गाम्बिया की भूमिका की तारीफ की। तारिक ने रोहिंग्या संकट को म्यांमार से शुरू हुआ बताते हुए कहा, 'यह संकट म्यांमार से शुरू हुआ। इसका हल म्यांमार में है।' उन्होंने कहा कि रखाइन राज्य में हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। वहां रोहिंग्याओं को गंभीर उल्लंघन और बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ रहा है।

एक नजर

श्रीपाद नाइक ने ऊर्जा सहयोग पर ईयू संसद की समिति के साथ बातचीत की

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने गुरुवार को यूरोपीय संसद (ईयू) की उद्योग, अनुसंधान एवं ऊर्जा समिति के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। विद्युत मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक में विद्युत क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की गई। इसे और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत क्षेत्र में बदलाव, कम कार्बन विकास, परमाणु ऊर्जा, कार्बन बाजार और नई प्रौद्योगिकियों सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।

मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने जारी पहलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में जारी मजबूती और सहयोग को बढ़ाने के अवसर तलाशे गए। इसमें भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में हुई महत्वपूर्ण प्रगति भी शामिल है। इस अवसर पर श्रीपाद नाइक ने भारत के तेजी से बदलते विद्युत क्षेत्र और मजबूत, भरोसेमंद तथा भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा प्रणाली विकसित करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लक्ष्यों को निर्धारित समय से काफी पहले हासिल करने, ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड समाधान अपनाने तथा परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और हरित हाइड्रोजन को आगे बढ़ाने में प्रगति की है। इस बैठक में भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी के प्रमुख स्तंभ के रूप में ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में सहयोग के महत्व को दोहराया गया। दोनों पक्षों ने सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों के लिए निरंतर संवाद, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान तथा तकनीकी और संस्थागत सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

केंद्र ने नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली निधि कंपनियों में निवेश से बचने की दी सलाह

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने लोगों को नियमों का पालन नहीं करने वाली निधि कंपनियों में निवेश करने से बचने की सलाह दी है। सरकार ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के माध्यम से आम जनता को नियमों का पालन न करने वाली निधि कंपनियों और उनके द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त रिटर्न (अधिक रिटर्न) के प्रलोभनों से सावधान रहने की सलाह दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि लोग ऊंचे रिटर्न का वादा करने वाली ऐसी कंपनियों के झांसे में न आएं तथा निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। मंत्रालय ने बताया कि निधि कंपनियां आपसी लाभ के लिए बनाई गई कंपनियां होती है, जिन्हें केवल अपने सदस्यों से जमा स्वीकार करने और उन्हें ऋण प्रदान करने की अनुमति है। मंत्रालय ने कहा कि ये कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 2013 और निधि नियम, 2014 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विनियमित होती हैं। मंत्रालय ने कहा, ''आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वित्तीय निर्णय लेते समय केवल एजेंट द्वारा किए गए असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न के वादों या अनौपचारिक आश्वासनों पर भरोसा न करें। उन्हें स्वतंत्र रूप से यह जांच करनी चाहिए कि संबंधित कंपनी को केंद्र सरकार ने निधि कंपनी के रूप में घोषित किया है या नहीं और निवेश की शर्तों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। कॉरपोरेट मंत्रालय के अनुसार, अबतक केवल 395 इकाइयों को निधि कंपनियों के रूप में घोषित किया गया है। इन निधि कंपनी के रूप में घोषित होने या विवरण अपडेट कराने के लिए इन कंपनियों को मंत्रालय में अनिवार्य रूप से एनडीएच-4 आवेदन को दाखिल करना होता है।

शिमला : नेशनल हाईवे पर बस-कार की टक्कर में एक परिवार के तीन लोगों की मौत

शिमला,एजेंसी। एक साथ सफर पर निकले परिवार के तीन लोगों की शिमला-मंडी नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में जान चली गई। घंडल के पास गुरुवार को एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस और कार की टक्कर में पति-पत्नी और दयानन्द की मां की मौत हो गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल है। कार में परिवार के चार लोग सवार थे। मृतकों की पहचान दयानन्द पुत्र ठाकरू राम (57), उनकी पत्नी हेमलता (52) और उनकी मां विद्यादेवी पत्नी ठाकरू राम (75), सभी निवासी गांव फान्जी, डाकघर घणागूघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार हादसा गुरुवार दिन में थाना बालूगंज अंतर्गत हुआ।

एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस बागीपुल से शिमला की ओर आ रही थी। इसी दौरान बस और कार के बीच टक्कर हो गई। कार में दो पुरुष और दो महिलाएं सवार थीं। टक्कर में दयानन्द और उनकी पत्नी हेमलता की मौके पर ही मौत हो गई। विद्यादेवी को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में कार चला रहा मृतक दयानन्द का बेटा मनीश गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है। बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस चौकी धामी की टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटना

की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने दुर्घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है। मृतकों में दयानन्द और उनकी पत्नी हेमलता के साथ दयानन्द की मां विद्यादेवी शामिल हैं।

शिमला के एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि घंडल के पास एचआरटीसी बस और कार की टक्कर में तीन लोगों की मौत हुई है। कार चालक गंभीर रूप से घायल है और उसका आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है। बस में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(ए) और 106(1) के तहत पुलिस थाना बालूगंज में अभियोग दर्ज किया है। पुलिस दुर्घटना के संबंध में आगामी जांच कर रही है।

खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी सहित चार की मौत

पूर्वी सिंहभूम। सोनारी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव स्थित दोमुहानी के समीप गुरुवार तड़के करीब तीन बजे हुए भीषण सड़क हादसे में चार युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार सड़क पर खराब होकर खड़े ट्रेलर के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों को निकालने के लिए गैस कटर का सहारा लेना पड़ा। मृतकों में झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह के अलावा सार्थक अग्रवाल, नमन गुप्ता और वंशिका खंडेलवाल शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार कार संख्या (जेएच05 डीएस 6450) मरीन ड्राइव से गुजर रही थी। दोमुहानी के पास सड़क पर खराब होकर खड़े ट्रेलर संख्या (जेएच02टी 3971)के पीछे कार अनियंत्रित होकर जा टकराई। बताया गया कि ट्रेलर बुधवार रात करीब 10 बजे से खराब होने के कारण सड़क पर खड़ा था। दुर्घटना के समय वहां पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा संकेतक की स्थिति को लेकर भी जांच की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर, सोनारी थाना प्रभारी संजय सुमन सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। कार इतनी बुरी तरह ट्रेलर में फंस गई थी कि बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गैस कटर से

कार को काटकर चारों शवों को बाहर निकाला गया। हादसे की भयावहता के कारण शव भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी अर्णव मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार तेज गति में थी और सड़क पर खड़े ट्रेलर से पीछे से टकरा गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। सड़क पर खड़े खराब वाहन के पीछे सुरक्षा संकेतक, चेतावनी व्यवस्था और प्रकाश की स्थिति की भी जांच की जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन घटनास्थल और एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के परिवार में भी हादसे की खबर से शोक की लहर है। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है।

मारुति सुजुकी का मानेसर में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू

नई दिल्ली। देश की अग्रणी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने विनिर्माण संयंत्रों को कम कार्बन उत्सर्जन वाला बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी अपने मानेसर संयंत्र में 300 किलोवाट क्षमता वाले हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र को चालू किया है। कंपनी ने गुरुवार को हरियाणा के मानेसर स्थित अपने संयंत्र में 300 किलोवाट क्षमता का हरित हाइड्रोजन संयंत्र पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया। यात्री वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि यहां तैयार होने वाली हरित हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर विनिर्माण प्रक्रियाओं में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा इस प्रोजेक्ट से कंपनी के मानेसर प्लांट में बनने वाली सोलर एनर्जी का ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल हो सकेगा। कंपनी ने कहा कि प्लांट में बनने वाली ग्रीन हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने इस प्रायोगिक परियोजना के बारे में कहा कि कंपनी विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विनिर्माण परिचालन में अपने कार्बन उत्सर्जन को मौजूदा 6.15 लाख टन से घटाकर वित्त वर्ष 2030-31 में 2.66 लाख टन करने

का लक्ष्य रखती है। उन्होंने बताया कि इस प्रायोगिक परियोजना से मिली सीख के आधार पर कंपनी हरियाणा व गुजरात स्थित अपने विनिर्माण संयंत्रों में भी हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना बना रही है। ताकेउची ने आगे कहा, ''हमारे 300 किलोवाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का चालू होना भारत सरकार के हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है।'' इसके अलावा उन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी हरियाणा स्थित खरखौदा स्थित संयंत्र में प्रतिदिन 10 टन क्षमता वाला बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के अंतिम चरण में है, इसे चालू वित्त वर्ष 2026-27 में चालू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने हाल में खरखौदा संयंत्र में एक मेगावाट-घंटे क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने हाल में चार संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इनके लिए 561 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में रियल एस्टेट सेक्टर की होगी अहम भूमिका: मुख्यमंत्री साय

रायपुर,एजेंसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुरुवार को नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 'बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़' कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के साथ प्रदेश में आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ आवास तथा मजबूत अधोसंरचना की आवश्यकता भी बढ़ रही है। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अपना घर प्रत्येक परिवार का सपना होता है।

समाज के हर वर्ग की आकांक्षा होती है कि उसके पास सुरक्षित और सुविधाजनक आवास हो। पिछले पौने तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर ने तेजी से प्रगति की है। आने वाले वर्षों में प्रदेश में बढ़ते निवेश, औद्योगिकीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी और नए शहरी केंद्रों के विकास के साथ इस क्षेत्र में संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों से कहा कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बनें और गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण में योगदान दें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विजन डॉक्यूमेंट 'छत्तीसगढ़ अंजोर' तैयार किया है।

राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अपार क्षमता है। प्रदेश का लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। यहां प्रचुर खनिज संपदा, पर्याप्त बिजली और जल संसाधन उपलब्ध हैं।

देश के प्रमुख क्षेत्रों से प्रदेश की कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है और यहां के मेहनतकश लोग हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' केवल एक कहावत नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सरलता, परिश्रम और सामर्थ्य की पहचान है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में कार्य करने के अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली को निकट से देखा है। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत आधुनिक अधोसंरचना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और जनकल्याण के नए अध्याय लिख रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित एवं दीर्घकालीन विकास के लिए स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रायपुर के साथ दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव क्षेत्र को जोड़ते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की योजना बनाई जा रही है। स्टेट कैपिटल रीजन से आवास, उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित होंगी तथा यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेगा।

असम कैबिनेट के बड़े फैसले, 11,000 करोड़ के सीमेंट निवेश को मंजूरी

गुवाहाटी,एजेंसी। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक सेवा भवन में हुई असम कैबिनेट की बैठक में वेटलैंड संरक्षण, कृषि, उद्योग, चाय श्रमिकों और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने असम सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन (स्विफ्ट) परियोजना को 796.88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लागू करने की मंजूरी दी। इसमें एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 637.504 करोड़ रुपये का ऋण और असम सरकार की ओर से 159.376 करोड़ रुपये का योगदान होगा। परियोजना के तहत कम से कम 102 जीर्ण-शीर्ण सामुदायिक बील का पुनरुद्धार और पुनर्वास किया जाएगा।

कैबिनेट ने जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के असम में 11,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को भी मंजूरी दी। कंपनी राज्य में क्लिंकर निर्माण इकाई और चार संबद्ध सीमेंट ग्राइंडिंग इकाइयां स्थापित करेगी। इससे करीब 2,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत राज्य सरकार ने प्रमोटर के अनिवार्य योगदान के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। एफपीओ, एफपीसी, पीएसी और सहकारी समितियों जैसी सामूहिक संस्थाओं के लिए 10 फीसदी का पूरा योगदान राज्य सरकार वहन करेगी। किसानों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों और जेएलजी जैसी व्यक्तिगत श्रेणियों के लिए सरकार 5 फीसदी योगदान देगी, जबकि शेष 5 फीसदी लाभार्थी

देंगे। गुवाहाटी के उलुबाड़ी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्पाइसेज बोर्ड की अत्याधुनिक प्रयोगशाला और सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किराया आधारित या प्रो-बोनो मॉडल को भी मंजूरी दी गई। कृषि विभाग, पीडब्ल्यूडी (बी) के समन्वय से स्पाइसेज बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजाइन और मानकों के अनुसार भवन का निर्माण करेगा। कैबिनेट ने असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड (एटीसीएल) के पात्र चाय बागान श्रमिकों और कर्मचारियों को 20 फीसदी बोनस देने को मंजूरी दी। इसके अलावा 166 अतिरिक्त मस्टर रोल, कैजुअल और फिक्स्ड पे कर्मचारियों को 1 सितंबर, 2026 से न्यूनतम् वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। एनएफएसए लाभार्थियों को अक्टूबर, 2026 के लिए 30 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। अक्टूबर में मसूर दाल और चीनी दोनों 100 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं, दुर्गा पूजा के अवसर पर अरुणोदय लाभार्थियों को अक्टूबर महीने में नियमित 1,250 रुपये के बजाय 1,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। कैबिनेट ने 17 अक्टूबर, 2026 को अतिरिक्त दुर्गा पूजा अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों की पात्र महिला सदस्यों के आधार नामांकन की सुविधा के लिए पहले जारी कार्यकारी आदेश को 31 मार्च तक पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई। श्रीभूमि जिले के पाथरकांदी में असम कृषि विश्वविद्यालय के तहत कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के लिए कृषि विभाग को 256 बीघा सरकारी भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024 के तहत पात्र लेकिन 30 सितंबर, 2026 की विस्तारित समयसीमा के भीतर पंजीकरण नहीं करा पाने वाली विनिर्माण इकाइयों के लिए राज्य पूंजी निवेश सब्सिडी को भी मंजूरी दी। मिसिंग स्वायत्त परिषद और सोनवाल कछारी स्वायत्त परिषद के चुनाव नवंबर में कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा हाजो राजस्व सर्किल के निज-गोंधमोउ गांव में 504 बीघा वीजीआर भूमि को उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के पक्ष में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इसके बदले पश्चिम बोंगशर मौजा के गांव नंबर 2 डोकानिया में 504 बीघा सरकारी भूमि को वीजीआर के रूप में आरक्षित किया जाएगा।

सूरत के नए सिविल अस्पताल के मेडिकल कालेज में रेजिडेंट डॉक्टर ने की आत्महत्या

सूरत,एजेंसी। सूरत के नए सिविल अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग में अध्ययनरत तृतीय वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर योगेंद्र दिलीप प्रजापति ने आत्महत्या कर ली। घटना दोपहर के समय डिसेक्शन हॉल में हुई। जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। योगेंद्र प्रजापति विवाहित थे और अपनी पत्नी के साथ सिविल अस्पताल परिसर स्थित छात्रावास में रहते थे। उनकी पत्नी भी होम्योपैथी की डॉक्टर हैं। योगेंद्र ने एमबीबीएस के बाद एनाटॉमी विषय में तीन वर्षीय रेजिडेंसी के लिए प्रवेश लिया था। उनकी परीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं और वे प्रशिक्षण के शेष हिस्से को पूरा कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल योगेंद्र ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर जांच कर रही है।

सिविल अस्पताल की अधीक्षक डॉ. पारुल वडगामा ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि एनाटॉमी विभाग के तृतीय वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर ने डिसेक्शन हॉल में

आत्महत्या की है। पुलिस की कार्रवाई के बाद घटना की पूरी जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जयेश ब्रह्मभट्ट ने बताया कि मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है। उनके अनुसार, मृतक छात्र के संबंध में इससे पहले कॉलेज प्रशासन के समक्ष कोई शिकायत नहीं आई थी। मेडिकल शिक्षा में एनाटॉमी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मानव शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ डिसेक्शन हॉल में शव के अध्ययन के माध्यम से शरीर की वास्तविक संरचना को समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)